राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण मंगलवार 03 नवंबर 2026 वर्ष-9,अंक-273 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

चारधाम में हेली सेवाओं पर ब्रेक, केदारनाथ शटल जारी रहेगी

- 11 ऑपरेटरों के विरोध के बाद फैसला, अगले सीजन में शुरू होंगी चार्टर उड़ानें, रिफंड होंगे रुपए

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड में चारधाम की चार्टर हेली सेवाओं पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है। 11 हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों के दो पायलट अनिवार्य करने के नियम के विरोध के बाद यह फैसला लिया गया है। सोमवार को उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण और



नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के बीच हुई बैठक में तय किया गया कि चार्टर हेली सेवाएं अब अगले सीजन में ही शुरू होंगी। हालांकि, केदारनाथ में शटल हेली सेवा जारी रहेगी। एजेंसी के सीईओ प्रतीक जैन ने बताया कि इस सीजन में चार्टर हेली सेवाओं की ज्यादा बुकिंग नहीं हुई थी। जिन यात्रियों ने बुकिंग कराई थी, उन्हें पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। केदारनाथ में सामान्य शटल हेली सेवाओं का संचालन जारी है। यहां एजेंसी ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कंट्रोल रूम बनाया है। यहां से मौसम और उड़ानों की पल-पल की जानकारी के आधार पर हेलीकॉप्टरों को उड़ान की अनुमति दी जा रही है। हालांकि, नए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होने के कारण लंबी दूरी की पर्सनल चार्टर सेवाएं बंद हैं। वहीं, गंगोत्री के कपाट 10 नवंबर, केदारनाथ और यमुनोत्री के 11 नवंबर, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 16 नवंबर को बंद होंगे।

एएपी छोड़ने वाले तीनों विधायक बीजेपी में शामिल

- तीनों ने पिछले दो दिन में इस्तीफा दिया, बीजेपी के हुए

अमृतसर (एजेंसी)। पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें अमृतसर नॉर्थ से कुंवर विजय प्रताप सिंह, समाना से चेतन सिंह जौड़ामाजरा और सनौर से हरमीत सिंह



पठानमाजरा शामिल हैं। बीजेपी जॉइन करने के बाद विधायक कुंवर ने कहा कि पंजाब में गैंगस्टर सरकार का हिस्सा बन गए हैं। फिरौती की इंडस्ट्री चल रही है। इन तीनों विधायकों ने पिछले 2 दिनों में एएपी से इस्तीफा दिया। रविवार को जौड़ामाजरा और पठानमाजरा के इस्तीफे के बाद सोमवार को कुंवर ने भी पार्टी छोड़ दी। कुंवर और पठानमाजरा ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। कुंवर को जून 2025 में एएपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 5 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया था।

आठ नए युद्धपोत से लैस होगी अपनी नौसेना

- 53,866 करोड़ रुपये होगा खर्च, रक्षा मंत्रालय ने किया करार

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत बढ़ाने के लिए देश में आठ अत्याधुनिक अगली पीढ़ी के कॉर्वेट युद्धपोत बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने इन युद्धपोतों के निर्माण और खरीद के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ कुल 53,866.50 करोड़ रुपए के करार किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस करार को लेकर खुशी जाहिर की है। 2 नवंबर को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इन करारों पर हस्ताक्षर किए गए। इन अगली पीढ़ी के कॉर्वेट युद्धपोतों में आधुनिक मिसाइलों, हथियारों और सेंसर प्रणालियों से लैस अत्याधुनिक क्षमताएं होंगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि इन जहाजों के निर्माण से अगले दस वर्षों में शिपयार्डों में लगभग 72 लाख पर्सन-डे और सहायक उद्योगों तथा कंपनी में 460 लाख पर्सन-डे के बराबर रोजगार पैदा होगा।



भारतीय नौसेना को मिली ताकत

इन युद्धपोत की मदद से नौसेना हवा, समुद्र की सतह और समुद्र के भीतर मौजूद खतरों से निपट सकेगी। इन युद्धपोतों के नौसेना में शामिल होने से उसकी अभियान क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। ये समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बनाने और पनडुब्बियों का पता लगाकर उनसे मुकाबला करने जैसे महत्वपूर्ण अभियानों में भूमिका निभाएंगे। ये युद्धपोत तटीय सुरक्षा मजबूत करने, समुद्र के किनारे उथले इलाकों में सैन्य अभियान चलाने और समुद्री क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने में भी मदद करेंगे। इनकी तैनाती से भारतीय नौसेना की समुद्र में मौजूदगी और निगरानी क्षमता को मजबूती मिलेगी। प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए निर्माण कंपनियों का चयन किया गया है। यह पहली ऐसी परियोजना है, जिसमें भारतीय नौसेना के स्वदेशी डिजाइन पर आधारित युद्धपोतों का निर्माण रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किया जाएगा।

कोलकाता स्थित जीआरएसई पांच युद्धपोतों का तैयार करेगी डिजाइन

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस परियोजना के तहत कोलकाता स्थित जीआरएसई पांच युद्धपोतों का निर्माण करेगा। वहीं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय नौसेना के लिए तीन युद्धपोत बनाएगा। खास बात यह है कि इन सभी युद्धपोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना खुद तैयार करेगी। इनका निर्माण देश के रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम करेंगे। इस परियोजना का फायदा केवल नौसेना की युद्धक क्षमता तक सीमित नहीं रहेगा। इससे देश के स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। परियोजना में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ निजी शिपयार्ड, भारतीय औद्योगिक साझेदारों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भी भागीदारी होगी।

राहुल गांधी के खेमे में असुरक्षा का माहौल

- कांग्रेस में प्रियंका गांधी को अलग-थलग करने की कोशिश

नई दिल्ली (एजेंसी)। बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर दरार आ गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि प्रियंका गांधी के बढ़ते प्रभाव की वजह से राहुल गांधी खेमे में असुरक्षा दिख रही है और प्रियंका गांधी को पार्टी में अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को इंडिया ब्लॉक की आयोजित रैली में प्रियंका गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। शनिवार को आयोजित सांकेतिक संसद की कार्यवाही में भी प्रियंका गांधी को अलग थलग करने की कोशिश की गई। जारी वीडियो मैसेज में प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस दो शक्ति केंद्रों में बंट चुकी है।



सीआईएसएफ ने सुरक्षा देने का 56 साल पुराना स्ट्रक्चर बदला

- अब पावर-स्टील प्लांट और बंदरगाह के लिए अलग-अलग सेक्टर, पहले जोन वाइज था



नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। फोर्स ने आज से अपने 56 साल पुराने टेरिटोरियल कमांड मॉडल को खत्म करके फंक्शनल सेक्टर मॉडल अपना लिया है। फोर्स अब तक जोन के हिसाब से काम करती थी। जैसे - मुंबई जोन के एक ही अधिकारी के पास पावर प्लांट भी होता था और कोयला खदान भी। इससे सुरक्षा मिली-जुली रहती थी। नए मॉडल में एक जैसी इंडस्ट्रियल यूनिट को एक ही छतरी के नीचे लाया गया है। यानी देशभर के सारे पावर प्लांट, सारे स्टील प्लांट, सारे बंदरगाह अलग-अलग डेडिकेटेड सेक्टर के अधीन होंगे।

सीआईएसएफ का दावा- काम अलग तो सुरक्षा भी अलग हो

अब तक सीआईएसएफ के फील्ड और प्रशासनिक ठिकाने जोनल आधार पर बने थे। इस वजह से एक ही फील्ड फॉर्मेशन अलग-अलग क्षेत्रों में बनी औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा संभालता था। उदाहरण के लिए, किसी फील्ड फॉर्मेशन के पास बिजली और कोयला क्षेत्र की इकाइयों की जिम्मेदारी एक साथ होती थी। सुरक्षा करने वाली सीआईएसएफ इकाइयां इसका अपवाद थीं।

फिर ट्रेन से कटा युवक, भोपाल में पटरी पर मिली लाश

मां-पत्नी और 2 बच्चों की गला काटकर हत्या

पुलिस घर पहुंची तब खुला हत्याकांड, कर्ज में डूबा था

भोपाल (एजेंसी)। भोपाल के मालीखेड़ी में सोमवार को असिस्टेंट लोको पायलट के किराए के घर में एक ही परिवार के 4 लोगों की लाश मिली है। सभी के गले कटे हुए थे। वहीं, घर के बेटे की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। शक है कि युवक ने पहले सभी की हत्या की, इसके बाद ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। छोला पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में परिवार के मुखिया पर कर्ज का दबाव था। घर में नरेंद्र की मां सरस्वती साहू (50), पत्नी सोमलता साहू (29), बेटी कृति साहू (10) और बेटे खुश



साहू (6) के शव मिले। सभी के सिर और गले पर चोट के निशान मिले हैं। एसीपी निशातपुरा शशांक जैन के मुताबिक, पुलिस को नरेंद्र के घर से निकलने का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसमें वह सुबह करीब 7.30 से 8 बजे के बीच घर से निकलता दिखाई दे रहा है। शक है कि सुबह-सुबह वारदात हुई है।

रेलवे ट्रैक पर युवक की लाश मिली, तब खुला मामला

परिवार के मुखिया नरेंद्र साहू (35) का शव सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र के चोपड़ा कलां स्थित रेलवे ट्रैक पर मिला था। सोमवार सुबह परिवार के एक रिश्तेदार को नरेंद्र की मौत की सूचना मिली। वह परिजन को जानकारी देने मालीखेड़ी स्थित घर पहुंचा, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। फोन पर भी किसी से संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद रिश्तेदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर घर में प्रवेश किया तो अंदर चार लोगों के शव मिले।

संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत शामिल, आगामी कार्ययोजना पर होगा मंथन

इंदौर में आरएसएस की तीन दिनी बैठक का आगाज

- 408 पदाधिकारी संगठन विस्तार-सामाजिक अभियानों की समीक्षा करेंगे

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की तीन दिवसीय बैठक सोमवार को डेली कॉलेज में शुरूहो गई। बैठक में संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले और सभी छह सह सरकार्यवाह सहित देशभर के करीब 408 प्रमुख पदाधिकारी शामिल हैं। 4 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान हुए कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ संगठन विस्तार और आगामी कार्ययोजना पर मंथन होगा। संघ ने पिछले एक साल में देशभर में 13 हजार से अधिक नई दैनिक शाखाएं जुड़ने की जानकारी दी है। इसके साथ ही 65 हजार से ज्यादा हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए। बैठक में इन आयोजनों से मिले अनुभवों के आधार पर आगे की गतिविधियों की दिशा तय की जाएगी। अखिल



भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि बैठक में संघ के 11 क्षेत्र और 46 प्रांतों से संघचालक, सह संघचालक, कार्यवाह, सह कार्यवाह, प्रचारक और सह प्रचारक शामिल हुए हैं। अंतिम दिन विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी और आंकड़े साझा किए जाएंगे।

युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरुकता अभियान

संघ की पिछली दो-तीन बैठकों में नशीली दवाओं के बढ़ते चलन पर चिंता जताई गई है। इस बार भी यह विषय एजेंडे में शामिल रहेगा। आंबेकर ने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर प्रयास जरूरी हैं। युवाओं को नशीली दवाओं से दूर रखने के लिए जागरुकता अभियान चलाने पर विचार होगा।

65 हजार से ज्यादा हिंदू सम्मेलन आयोजित

शताब्दी वर्ष के दौरान देशभर में 65 हजार 660 हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया गया। आंबेकर के मुताबिक, शहरों में बस्ती स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में आठ-दस गांवों को मिलाकर बनाए गए मंडल स्तर पर ये सम्मेलन हुए। कई जगह दो-तीन मंडलों को मिलाकर भी आयोजन किए गए। उन्होंने बताया कि इन सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा और समाज की ओर से समर्थन मिला। लोगों ने संघ की शाखाओं से जुड़ने की इच्छा जताई। सामाजिक संस्थाओं और संगठनों ने भी अपने कार्यक्रमों में स्वयंसेवकों के अनुभवों का सहयोग लेने की इच्छा व्यक्त की है। बैठक में इन सम्मेलनों से मिले अनुभवों और सामाजिक सहभागिता की समीक्षा होगी। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी भी रही। अब इस अनुभव के आधार पर महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रमों और उपक्रमों पर विचार किया जाएगा।

एमपी में शराब तस्करों ने टीआई को कुचला, मौत

- इंदौर-बैतूल हाईवे पर तस्करी रोकने गए थे टीआई दिलीप पुरी

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के देवास में अवैध शराब भरे वाहन (ट्रक) ने खातेगांव टीआई दिलीप पुरी को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल पुरी को अस्पताल ले जाया गया। यहां करीब दो घंटे तक इलाज के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुरी रविवार रात करीब डेढ़ बजे अवैध शराब की तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करने टीम के साथ इंदौर-बैतूल हाईवे पहुंचे थे। नेमावर पुलिस भी इसी ट्रक का पीछा कर रही थी। पुलिस टीम को ट्रक डिवाइडर के किनारे खड़ा मिला। पुरी ने ट्रक ड्राइवर से बाहर आने को कहा तो वो ट्रक को डिवाइडर पर चढ़ाकर आगे बढ़ाने लगा। इस दौरान पिछला पहिए पुरी के ऊपर चढ़ गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टीआई पुरी की पत्नी को एसआई पद पर अनुकंपा नियुक्ति और परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।



रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए संकेत, जल्द मिलेगी अनुमति

बेंगलुरु-पुणे होगा देश का अगला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर

बेंगलुरु (एजेंसी)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु और मुंबई को जोड़ने वाली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की पहली सेवा को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ, रेल मंत्री ने संकेत दिया कि प्रस्तावित बेंगलुरु-पुणे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अगली उच्च गति रेल परियोजनाओं में शामिल हो सकता है। अन्य बुलेट परियोजनाएं भी शुरू की जानी हैं। उन्होंने कहा, भविष्य में बुलेट ट्रेन से बेंगलुरु से चेन्नई पहुंचने में सिर्फ 73 मिनट लगेंगे—एक घंटा 13 मिनट। ये दोनों शहर एक शहर जैसे हो जाएंगे। रेल मंत्री वैष्णव ने रविवार को यह भी घोषणा की कि कर्नाटक के लिए अगली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बेंगलुरु से चलेगी। यह उत्तर कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों को हुब्बली की ओर जोड़ने के बाद पुणे और मुंबई जाएगी।



अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस

उन्होंने बताया कि बेंगलुरु-मंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस अगले कुछ हफ्तों में शुरू की जाएगी। इस मार्ग पर विद्युतीकरण और परीक्षण का काम पूरा हो चुका है। आठ मोटर कार और चार ट्रेलर कार कोच समेत 16 कोच वाली बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की पहली सेवा को हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन की उद्घाटन विशेष सेवा बेंगलुरु के सर एम विश्ववेश्वरैया टर्मिनल (एसएमवीटी) से रवाना हुई। यह सोमवार सुबह 6.15 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पहुंचेगी।

चार हजार किमी के बुलेट ट्रेन गलियारों को मंजूरी

वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चार हजार किलोमीटर के बुलेट ट्रेन गलियारों को मंजूरी दी है। आने वाले वर्षों में 3,000 किलोमीटर के और बुलेट ट्रेन गलियारों की घोषणा होगी। बेंगलुरु-पुणे जैसे कई और गलियारे होंगे, जो पूरे कर्नाटक को जोड़ेंगे—बेंगलुरु से हुब्बली होते हुए पुणे तक। वह गलियारा भी शामिल होगा। प्रस्तावित दक्षिणी बुलेट ट्रेन कारिडोर को मंजूरी मिल चुकी है। यह बेंगलुरु, हैदराबाद, अमरावती व चेन्नई को जोड़ेगा और दक्षिण के प्रमुख आर्थिक व प्रौद्योगिकी केंद्रों को करीब लाएगा। रेल मंत्री ने कहा, दक्षिणी बुलेट ट्रेन कारिडोर दक्षिण भारत के राज्यों के लिए यह बड़ा गुणक साबित होगा। प्रस्तावित यात्रा समय का संकेत देते हुए वैष्णव ने कहा कि बेंगलुरु से चेन्नई की यात्रा में सिर्फ 73 मिनट, जबकि बेंगलुरु से हैदराबाद पहुंचने में दो घंटे 10 मिनट लगेंगे। बेंगलुरु-मंगलुरु वंदे भारत सेवा के बारे में मंत्री ने कहा कि जरूरी विद्युतीकरण और परीक्षण का काम पूरा हो चुका है और ट्रेन अगले कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएगी।

राजस्थान में करंट लगने से आठ मजदूरों की मौत

- झुंझुनूं में सड़क बनाते समय मशीन हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई

उदयपुरवाटी (एजेंसी)। राजस्थान के झुंझुनूं जिले के छापोली गांव में सोमवार सुबह सड़क बना रहे 8 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। 5 अन्य मजदूर झुलस गए। हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। उदयपुरवाटी के एसएचओ रामपाल ने बताया- सड़क पर काम कर रही रोड़ी-बजरी मिक्सर मशीन का हाइड्रोलिक जैक ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तार से छू गया। इससे मशीन में करंट फैल गया और वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार, छापोली में कदम कुंड की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान रोड़ी मिलाने वाली मशीन 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन से टकरा गई। मशीन के बिजली लाइन की चपेट में आने से वहां काम कर रहे मजदूर करंट की चपेट में आ गए। इस हादसे में आठ मजदूरों की मौत हो गई। वहीं, पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।



Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

रामलीला मैदान से लोकतंत्र की हुंकार

(लेखक-कुमार कृष्णन/)

दिल्ली का रामलीला मैदान 1 नवंबर 2026 को एक बार फिर भारतीय राजनीति के केंद्र में था। इंडिया गठबंधन की महारैली केवल विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि मतदाता सूची, चुनावी पारदर्शिता, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर उठे सवालों का राष्ट्रीय मंच भी थी। वोट बचाओ, देश बचाओ के नारे के साथ आयोजित इस रैली में उमड़ी भीड़ ने यह संकेत दिया कि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवाद को संसद और राजनीतिक बयानबाजी से आगे ले जाकर जनांदोलन का रूप देना चाहता है। रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव सहित विभिन्न राज्यों के नेताओं की मौजूदगी ने इसे व्यापक राजनीतिक स्वरूप दिया। अलग-अलग विचारधाराओं और क्षेत्रीय हितों वाले दलों का एक मंच पर आना अपने आप में महत्वपूर्ण था। इस आयोजन में बिहार कांग्रेस के नेताओं और पिछड़ा वर्ग विभाग के पदाधिकारियों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही।

रैली की प्रमुख तस्वीर राहुल गांधी की रही। भारी भीड़ के कारण पदयात्रा के बजाय वे खुले वाहन से रामलीला मैदान पहुंचे। उनके साथ प्रियंका गांधी और दूसरे विपक्षी नेता भी थे। सड़कों पर उमड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच खुले वाहन से नेताओं का आगे बढ़ना जनसंपर्क और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बना।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर तीखा हमला किया। उनका आरोप था कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों के माध्यम से लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। राहुल गांधी का कहना था कि यदि योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाते हैं तो चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। उनके भाषण का राजनीतिक संदेश स्पष्ट था। कांग्रेस इस मुद्दे को केवल निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे संविधान, नागरिक अधिकार और सत्ता की जवाबदेही से जोड़ रही है। हालांकि विपक्ष के आरोपों को प्रमाणित तथ्य मानने के बजाय उनकी स्वतंत्र जांच और आयोग के जवाब के संदर्भ में देखना जरूरी है।

इस महारैली का एक अलग और आकर्षक दृश्य पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव (राजेश रंजन) का तिरंगा मार्च रहा। वे हजारों साधु-संतों और समर्थकों के साथ रामलीला मैदान पहुंचे। हिमाचल भवन और कनॉट प्लेस से मिंटो ब्रिज होते हुए आगे बढ़े इस काफिले में साधु-संतों और कार्यकर्ताओं के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा था। पप्पू यादव ने आंदोलन को लोकतंत्र, संविधान और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा से जोड़ते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखे राजनीतिक हमले किए। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल या व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और आम लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए है।

इस मार्च का महत्व केवल उसमें शामिल लोगों की संख्या में नहीं था। साधु-संतों की भागीदारी ने राजनीतिक विरोध को व्यापक सामाजिक स्वरूप देने का प्रयास किया। भारतीय राजनीति में धार्मिक-सामाजिक समूहों की सार्वजनिक भागीदारी का अपना इतिहास है। इस अवसर पर तिरंगा लेकर उनका मताधिकार और संविधान से जुड़े सवालों पर मार्च करना एक अलग संदेश दे रहा था। पप्पू यादव की इस पहल ने रैली में सामाजिक भागीदारी का एक नया पक्ष जोड़ा।

रामलीला मैदान की महारैली के संदर्भ में बिहार कांग्रेस की भागीदारी को विशेष महत्व देना चाहिए। बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। ऐसे में बिहार प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों की सक्रियता को केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम में भागीदारी के रूप में नहीं देखा जा सकता।

बिहार प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग की उपाध्यक्ष सोनी कुमारी, विभाग के अध्यक्ष अनुराग चंदन और मुंगेर जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष राकेश कुमार मंडल की भूमिका इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। इन पदाधिकारियों के सामने चुनौती है कि राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जा रहे लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के सवालों को बिहार के गांवों, कस्बों और जिला मुख्यालयों तक पहुंचाएं। सोनी कुमारी की भूमिका महिला प्रतिनिधित्व के सवाल से भी जुड़ती है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के सामने शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी की अनेक चुनौतियां हैं। संगठन में महिलाओं की मौजूदगी तभी सार्थक होगी जब उन्हें निर्णय लेने और जनसंपर्क अभियान संचालित करने में वास्तविक भूमिका मिले। राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व केवल पदों की संख्या नहीं, बल्कि नेतृत्व और अधिकार की भागीदारी भी है। अनुराग चंदन के नेतृत्व में ओबीसी विभाग के सामने सामाजिक न्याय के मुद्दों को व्यापक राजनीतिक कार्यक्रम से जोड़ने की जिम्मेदारी है। जातीय जनगणना, आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों की समानता जैसे प्रश्नों पर संगठन को लगातार संवाद करना होगा। मतदाता सूची में किसी योग्य नागरिक का नाम छूटना भी सामाजिक न्याय से जुड़ा सवाल है, क्योंकि मताधिकार नागरिक की राजनीतिक पहचान और भागीदारी का आधार है। मुंगेर जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष राकेश कुमार मंडल की भूमिका इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। इन पदाधिकारियों के सामने चुनौती है कि राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जा रहे लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के सवालों को बिहार के गांवों, कस्बों और जिला मुख्यालयों तक पहुंचाएं। सोनी कुमारी की भूमिका महिला प्रतिनिधित्व के सवाल से भी जुड़ती है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के सामने शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी की अनेक चुनौतियां हैं। संगठन में महिलाओं की मौजूदगी तभी सार्थक होगी जब उन्हें निर्णय लेने और जनसंपर्क अभियान संचालित करने में वास्तविक भूमिका मिले। राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व केवल पदों की संख्या नहीं, बल्कि नेतृत्व और अधिकार की भागीदारी भी है। अनुराग चंदन के नेतृत्व में ओबीसी विभाग के सामने सामाजिक न्याय के मुद्दों को व्यापक राजनीतिक कार्यक्रम से जोड़ने की जिम्मेदारी है। जातीय जनगणना, आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों की समानता जैसे प्रश्नों पर संगठन को लगातार संवाद करना होगा। मतदाता सूची में किसी योग्य नागरिक का नाम छूटना भी सामाजिक न्याय से जुड़ा सवाल है, क्योंकि मताधिकार नागरिक की राजनीतिक पहचान और भागीदारी का आधार है। मुंगेर जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष राकेश कुमार मंडल की जिम्मेदारी भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मंचों पर उठे सवालों को स्थानीय स्तर तक ले जाना जिला संगठनों का काम है। मतदाता सूची में नामों की जांच, नए मतदाताओं का पंजीकरण और नाम हटाए जाने से संबंधित शिकायतों में नागरिकों की सहायता जैसे कामों से ही यह अभियान व्यावहारिक रूप ले सकता है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के नेतृत्व में प्रदेश संगठन के सामने भी यही चुनौती है। संगठनात्मक विस्तार के साथ पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महिला और युवा वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। बिहार कांग्रेस को गठबंधन की राजनीति के साथ अपनी स्वतंत्र संगठनात्मक पहचान और जमीनी सक्रियता भी मजबूत करनी होगी।विभिन्न प्रदेशों की भागीदारी और विपक्षी एकता रामलीला मैदान की रैली की विशेषता विभिन्न राज्यों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं की भागीदारी थी। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, बिहार से तेजस्वी यादव, झारखंड से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, जम्मू-कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला तथा महबूबा मुफ्ती और दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से आए नेताओं ने इस आयोजन को राष्ट्रीय स्वरूप दिया। वामपंथी दलों की मौजूदगी ने भी विपक्षी एकजुटता को व्यापक बनाया। इस भागीदारी के पीछे अलग-अलग राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर तृणमूल कांग्रेस की आशंकाएं हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने नाम हटाए जाने के सवाल उठाए हैं। बिहार में भी मतदाता अधिकार और चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। झारखंड सहित दूसरे राज्यों के नेताओं ने भी इस प्रश्न को लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ा। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे को उठाया। तेजस्वी यादव ने इसे मतदाताओं के अधिकारों की लड़ाई बताया। ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इस तरह अलग-अलग प्रदेशों की राजनीतिक चिंताएं एक साझा मंच पर सामने आईं। हालांकि विपक्षी एकता की वास्तविक परीक्षा मंच साझा करने के बाद शुरू होती है। राज्यों में इन दलों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। सीटों का बंटवारा, नेतृत्व और साझा चुनावी रणनीति जैसे सवाल अभी भी मौजूद हैं। यदि यह एकता केवल केंद्र सरकार के विरोध तक सीमित रहती है तो उसका स्थायित्व कठिन होगा। उसे रोजगार, महंगाई, सामाजिक न्याय और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर भी साझा कार्यक्रम बनाना होगा।

रैली का केंद्रीय मुद्दा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का आरोप था। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और बड़ी संख्या में योग्य मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं।

विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई। उसका आरोप है कि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल हैं। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग का तर्क है कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए मृत, दोहरे और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाना आवश्यक है।

दोनों पक्षों के दावों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। यदि किसी योग्य नागरिक का नाम गलती से हटाया गया है तो उसे नाम वापस जुड़वाने की सरल प्रक्रिया मिलनी चाहिए। आयोग को राज्यवार आंकड़े, नाम हटाने के कारण और शिकायतों के निपटारे की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा पारदर्शिता और निष्पक्षता से ही कायम रहती है।

महारैली से एक दिन पहले विपक्षी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विरुद्ध प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोग की कार्यवाही आयोजित की थी। इस आयोजन के माध्यम से विपक्ष ने निर्वाचन आयोग की जवाबदेही का सवाल उठाया। यह वास्तविक संवैधानिक महाभियोग नहीं, बल्कि राजनीतिक विरोध दर्ज कराने का प्रतीकात्मक तरीका था।

दूसरी ओर भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक दुष्प्रचार बताया। भाजपा नेताओं का तर्क है कि चुनावी पराजय या राजनीतिक असफलता के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना विपक्ष की रणनीति है। इस राजनीतिक टकराव का समाधान आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया और तथ्यों के सार्वजनिक परीक्षण से ही संभव है।

रामलीला मैदान की महारैली ने विपक्षी दलों को एक साझा मंच दिया है। लेकिन इस आयोजन की सफलता का आकलन केवल भीड़ से नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी के नेतृत्व, पप्पू यादव के तिरंगा मार्च, क्षेत्रीय दलों की भागीदारी और बिहार कांग्रेस के ओबीसी नेतृत्व की सक्रियता को आगे ठोस संगठनात्मक कार्यक्रम में बदलना होगा।

संपादकीय

क्रूर होती मासूमियत

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक आठ साल का बच्चा, छह साल की बच्ची को क्रूरता के साथ पीटता-कुचलता नजर आया। पंचकूला के एक निजी स्कूल में घटी इस घटना ने हर संवेदनशील इंसान को झकझोरा है। स्कूली छात्रों में नोक-झोंक, वाद-विवाद, मतभेद-मनभेद हमेशा होते रहे हैं। ऐसे में टीचर या अभिभावक तक शिकायत करके बात खत्म हो जाती थी। लेकिन यह आठ साल का बच्चा, जिस क्रूरता से केजी की बच्ची को खत्म करने की कोशिश में लगा था, उसने हमारे नीति-नियंताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और आम लोगों तक को स्तब्ध कर दिया। बच्चे ने इस हमले को सुनियोजित तरीके से, समय-जगह का चुनाव करके अंजाम दिया। वह समय चुना जब उसके अपराध को देखने वाला कोई नहीं था। विज्ञान का धन्यवाद, जिसने सीसीटीवी कैमरा हमें उपलब्ध कराया। अन्यथा कोई विश्वास नहीं करता कि इतना छोटा बच्चा एक पेशेवर अपराधी की तरह वारदात को अंजाम देगा। हो सकता था रिकॉर्डिंग न होने पर किसी निर्दोष के सिर इस हमले का आरोप लग जाता। निस्संदेह, इस हादसे में स्कूल प्रशासन की गंभीर चूक है। आखिर स्कूल से अंतिम बच्चे के बाहर निकलने तक सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभायी गई? अब स्कूल पढ़ने जा रही छोटी बच्चियों व बच्चों के मां-बाप इस घटना से भयाक्रांत हैं कि क्या उनका बच्चा स्कूल में सुरक्षित है? शिक्षकों को भी इस बात को गंभीरता से समझना होगा कि बदलते दौर में बच्चे पहले जैसे नहीं रहे। शिक्षक-अभिभावक से ज्यादा उन्हें आज जो सबसे ज्यादा ज्ञान बांट रहा है, वह मोबाइल है। जो तमाम तरह की हिंसा सिखाने का स्रोत बन गया है। इस घटना के बाद, इस आठ साल के छात्र की क्रूर व्यवहार की वजह उसका मोबाइल पर हिंसक फ्री-फायर गेम खेलना बताया जा रहा है। जो एक ऑनलाइन एक्शन व शूटिंग आधारित गेम है। जिसमें खिलाड़ी हथियार, गोलियों और अन्य घातक साधनों से प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला करते हैं। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि बच्चों को छोटी उम्र में मोबाइल उपलब्ध कराने के घातक परिणाम भी हो सकते हैं। आमतौर पर अभिभावक अपने काम करने या आराम करने के दौरान बच्चों को बहलाने के लिये मोबाइल पकड़ा देते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि इंटरनेट पर प्रसारित होने वाले हिंसक कार्यक्रम बच्चों को कितने गहरे तक प्रभावित करते हैं। बच्चे का दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह से होता है। उस पर जैसी छाप बचपन में पड़ती है, वही भविष्य में उसकी सोच व जीवन की दिशा निर्धारित करती है। जिस पश्चिमी संस्कृति व जीवन शैली पर आधारित गेम्स का इन दिनों मोबाइल पर प्रचलन है, वे बच्चों को संवेदनहीन और निर्मम बना रहे हैं। बच्चों में लगातार अधैर्य, अशांति व आक्रामकता बढ़ रही है। बच्चों को ये लगता है कि व्यावहारिक जीवन में भी ऐसा ही व्यवहार सामान्य बात है। बच्चों के व्यवहार में आ रहा यह बदलाव एक घातक संकेत है। हमारे नीति-नियंताओं और शिक्षकों-अभिभावकों को सजग-सतर्क होकर इस संकट के समाधान की दिशा में गंभीर प्रयास करना होगा।

पुरानी फिल्मों का लौटता क्रेज अत्यंत सुखद

(लेखिका- आयुषी दवे)

महज 115 वर्षों में भारतीय फिल्मों ने कई दौर देखे। टॉकीजों में हाउस फुल से लेकर ब्लैक में टिकट का भी मजेदार जमाना था। धीरे-धीरे तकनीक ने इस इण्डस्ट्री को नया ठौर दिया। एक समय थ्री डी फिल्मों का भी जबरदस्त क्रेज रहा। लेकिन लोगों, खासकर भारत की बात करें तो पुरानी फिल्में और पुराने गीत ही लोगों की जुबान पर हमेशा छाए रहे। चाहे सफर में लक्जरी कार में हों या ट्रेन में मोबाइल पर बज रहे गीत ज्यादातर पुराने और 60 से 90 दशक के बीच के ही बजते सुनाई देते हैं। तमाम बदलाव व चुनौतियों के बाद धमाकेदार शुरुआत के बावजूद नए दौर के गानों ने वो मुकाम कभी हासिल ही नहीं किया जो कि पुराने गानों का अब तक बना हुआ है। कमोवेश अब ऐसा ही ट्रेन्ड पुरानी फिल्मों को लेकर लौट रहा है। भले ही तकनीक ने बहुत बड़ा बदलाव किया और फिल्मों को एक से एक आइडिया दिए लेकिन बावजूद तमाम फैन्टासी, थ्रिल, मिक्सिंग, वीडियो एडिटिंग, एनीमेशन के पुरानी और सीधी सपाट शूटिंग से बनी फिल्मों का आकर्षण कमा जरूर लेकिन घटा नहीं।

इस बीच कम से चार-पांच पीढ़ियों का अंतर भी आया। 3 घंटे की जगह 2 घंटे की फिल्में बनने लगीं, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर फिल्में बनीं और सिनेमाघरों के साथ-साथ मल्टीफ्लेक्स, ओटीटी तथा होम थियेटर का भी चलन शुरू हो गया। नई पीढ़ी का फिल्मों उसमें विशेषकर गीत-संगीत के प्रति बदलता नजरिया और जायका भी दिखा।पश्चिमीकरण के प्रभावों में आकरन केवल भारत बल्कि दुनिया भर में तमाम संगीत, संस्कृतियां इससे प्रभावित हुईं और मूल स्वरूप तक को खो दिया। जैज, रॉक एंड रोल, और कंट्री-वेस्टर्न ने धमाल मचाना शुरू किया। सुमधुर भारतीय संगीत परंपरा ने वो दौर भी देखा जब तेज और विदेशी वाद्य यंत्रों के साथ मिक्स संगीत कल्चर ने खूब हल्ला मचाया।

बीच-बीच मेंफूहड़पन का भी एक दौर भी चला। तब भी पुराने गानों की लोकप्रियता में कमीं नहीं आई। रेडियो सीलोन जो बाद में श्री ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन के नाम से प्रसारण करने लगा से प्रसारित बिनाका गीत माला ने तो धूम ही मचा दी।यह शो 1952 से 1988 तक रेडियो सीलोन पर हर बुधवार को प्रसारित हुआ। इसने भी भारतीय गीतों को बड़ी उंचाई दी। लोग इतने दीवाने थे कि सारा काम निपटा कागज, पेन ले गीतों की ग्रेडिंग के लिए बैठ जाते। हालांकि बाद में 1989 से 1994 तक इसे विविध भारती से प्रसारित किया लेकिन तब तक टेलीविजन का युग भारत में आ चुका था और इस कार्यक्रम की लोकप्रियता घटती गई। बावजूद इसके सरकारी नियंत्रण के शुरुआती चैनल दूरदर्शन पर भी भारतीय फिल्मों के गीतों के कई कार्यक्रम चित्रहार और अलग-अलग नामों से आए और खासे लोकप्रिय हुए। इनमें भी पुराने गीतों का जलवा रहा।

बीच-बीच मेंफूहड़पन का भी एक दौर भी चला। तब भी पुराने गानों की लोकप्रियता में कमीं नहीं आई। रेडियो सीलोन जो बाद में श्री ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन के नाम से प्रसारण करने लगा से प्रसारित बिनाका गीत माला ने तो धूम ही मचा दी।यह शो 1952 से 1988 तक रेडियो सीलोन पर हर बुधवार को प्रसारित हुआ। इसने भी भारतीय गीतों को बड़ी उंचाई दी। लोग इतने दीवाने थे कि सारा काम निपटा कागज, पेन ले गीतों की ग्रेडिंग के लिए बैठ जाते। हालांकि बाद में 1989 से 1994 तक इसे विविध भारती से प्रसारित किया लेकिन तब तक टेलीविजन का युग भारत में आ चुका था और इस कार्यक्रम की लोकप्रियता घटती गई।

लेकिन 1970 के दौर से ही पश्चिमी संगीत का प्रभाव दिखने लगा। नई पीढ़ी धीरे-धीरे इसकी गिरफ्त में आने लगी। टेप रिकॉर्डर के आते ही फिर नए-पुराने गीतों की अघोषित प्रतिस्पर्धा भी काफी दिखी। शादी-विवाह में भी यह सब दिखा। लेकिन पिछले एक-डेढ़ दशक से एक बार फिर न केवल पुराने गीत-संगीत वापस सुनाई देने लगे हैं बल्कि रिमिक्स के नाम पर उसका सम्मिश्रण अलग ही तरह की अनुभूति देने लगा।3 मई 1913 को भारतीय सिनेमा की पहली फीचर फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' प्रदर्शित हुई जो गूंगी थी यानी बिना आवाज की फिल्म। इसका निर्माण भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के ने किया था। तब से लेकर अब तक बॉलीवुड का सफर हमेशा ऊंचाइयों को ही छूता रहा। इस बीच दक्षिण, पंजाब, भोजपुरी सहित तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में भी फिल्मों का भी जबरदस्त दौर आया जो अब भी जारी है। लेकिन पूरे भारत की बात करें तो फिल्म और संगीत में अब भी पुराने गीत-संगीत का धमक और जादू जस का तस है। लेकिन लोगों का पुरानी फिल्मों के प्रति बदलता नजरिया और आकर्षण भले ही नई तकनीक ओटीटी और इण्टरनेट के जरिए होम थियेटर के प्रभाव बढ़ा लेकिन यह सच है कि परन्तु पुरानी फिल्मों का क्रेज धीरे-धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है।

मदर इण्डिया, उपकार, पूरब-पश्चिम, गुड्डी, हाथी मेरे साथी, आनन्द, गाइड, दीवार, कटी पतंग, हरे रामा हरे कृष्णा, लैला-मजनू, मुगल-ए-आजम, शोले, बॉबी जैसी ढेरों फिल्मों ने तबकी युवा और अबकी बूढ़ी हो चुकी पीढ़ी पर अमिट छाप छोड़ी। हां, नई तकनीक उसमें भी खासकर इण्टरनेट के प्रभाव से कुछ वर्षों तक ये फिर से बॉक्स में बंद जैसी स्थिति में जरूर थीं। लेकिन सुकून की बात है कि एक बार फिर पुरानी और संदेश देती लोकप्रिय फिल्मों का दौर लौट रहा है। इसके पीछे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव और दमदार स्क्रिप्ट है। कहानियां सच के धरातल पर दिखती हैं। शायद यही वजह है कि पुरानी फिल्में थियेटर से लेकर मल्टीफ्लेक्स पर फिर अपना जलवा बिखेरने को तैयार हैं। निश्चित रूप से भारतीय परिवेश, संस्कार, रीति-रिवाज वो चाहे देश के पूरब से पश्चिम हो या उत्तर से दक्षिण लोग वापस जुड़ रहे हैं और जानना-समझना चाहते हैं जो बेहद सुकून की बात है। नई पीढ़ी का पुरानी भारतीय फिल्मों के प्रति लगाव-झुकाव बेहद सुखद संदेश है।

(लेखिका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन में इंजीनियर हैं)

कोई भी परिस्थिति हो, ये काम कभी बंद ना करें..



अपने विचारों का मूल्यांकन करना कभी भी बंद न करें, क्योंकि विचारों का प्रवाह अनवरत और कभी-कभी अत्यधिक भी हो जाता है। हर नया विचार पुराने को चुनौती देता है। यहीं से भ्रम भी पैदा होता है और कभी-कभी अधिक विचार आने से निर्णय भी गलत हो जाते हैं। रावण के साथ यही हुआ। वह बहुत विद्वान था। लिहाजा उसके भीतर विचारों की भरमार थी।

सुंदरकांड का दृश्य है। रावण के दरबार में हनुमानजी निर्भीक खड़े थे। दोनों का वार्तालाप शुरू होता है।

कह लंकेस कवन तैं कीसा। केहि कें बल घालेहि बन खीसा।।

की धौं श्रवन सुनेहि नहिं मोही। देखउं अति असंक सठ तोही।।

लंकापति रावण ने कहा - रे वानर! तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश नहीं सुना? रे शठ! मैं तुझे अत्यंत निरूशंक देख रहा हूं।

मारे निसिचर केहिं अपराधा। कहु सठ तोहि न प्रान कइ बाधा।। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? यहां रावण ने हनुमानजी से पांच प्रश्न पूछे। इन शब्दों में अहंकार भरा हुआ था। रावण ने अपने ही विचारों को शब्दों से जोड़ने के लिए अहंकार का सेतु बनाया, जबकि विश्लेषण के साथ शब्द प्रस्तुत करने थे, क्योंकि सामने हनुमानजी खड़े थे।

हनुमानजी की विशेषता यही थी कि वे अपने विचारों का मूल्यांकन करते रहते थे। दरअसल रावण यह मानता ही नहीं था कि वह अहंकारी है। उसके हिसाब से तो जो वह कर रहा होता था, वही सही माना जाए। उसके पास सबकुछ होने के बाद भी वह अव्वल दर्जे का भिखारी था। यहीं से हनुमानजी उसे बुद्धि का दान देना शुरू करते हैं।

लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

(लेखक- सनत जैन)

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह एक असाधारण राजनीतिक स्थिति है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोकतंत्र बचाने का नारा लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को इंडिया गठबंधन की वोट बचाओ, देश बचाओ रैली और इसके जवाब में भाजपा का देशव्यापी लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान इस बात का संकेत है। चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक संघर्ष अब संसद की सीमाओं से बाहर निकलकर सड़कों तक पहुंच गया है। इंडिया गठबंधन की रैली की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राजद, वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं के नाम काटने तथा चुनाव के दौरान कंप्यूटर की सहायता से भारी हेरफेर किए जाने के आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए और सवाल उठाए गए। इस आयोजन में राजनीतिक नेताओं के साथ सामाजिक संगठनों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, युवाओं और उन मतदाताओं ने भी भागीदारी की, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गये थे। 31 अक्टूबर को आयोजित प्रतीकात्मक जन संसद में भी विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ छह आरोपों के साथ प्रस्ताव पारित किया। विपक्ष की मांग है, ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाये। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच हो। इस पूरे विवाद की जड़ एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के अनुसार 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रारूप मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए। सबसे गंभीर बात यह है कि चुनाव आयोग के ही दो अन्य आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई बार आयोग के भीतर प्रक्रियाओं और फैसलों पर लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। अखबार की रिपोर्ट में ऐसी 14 आपत्तियों का उल्लेख है। इससे चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। ज्ञानेश कुमार एक तरफा फैसला ले रहे थे। राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में अपने भाषण के दौरान ज्ञानेश कुमार और चुनावी प्रक्रिया को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी में शामिल लोगों को जवाबदेह बनाया जाएगा। ममता बनर्जी ने भी बताया पश्चिम बंगाल का चुनाव किस तरह लूटा गया है, डकैती डाली गई है। रैली में वक्ताओं ने बड़े आक्रामक तरीके से चुनाव आयोग द्वारा की गई गडबड़ियों का उल्लेख किया। दूसरी ओर भाजपा ने विपक्ष के आंदोलन को अराजकता फैलाने की कोशिश बताते हुए देशभर में जवाबी कार्यक्रम आयोजित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के समर्थन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अलग-अलग राज्यों में पदयात्राओं और सभाओं के माध्यम से विपक्ष के ऊपर हमला किया है। यह भी सत्य है कि इस बार विपक्ष के साथ भारी भीड़ है, जनमानस का समर्थन प्राप्त है। उसके मुकाबले में भाजपा की पदयात्रा और रैली में वह भीड़ देखने को नहीं मिली जो होना चाहिए थी। यह राजनीतिक संघर्ष अब केवल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी अथवा कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं रह गया है। इसका सीधा संबंध देश की संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़ गया है। चुनाव आयोग पर आरोप लगना और उन आरोपों का राजनीतिक रूप से जवाब देना, अलग बात है। आयोग की निष्पक्षता पर आम जनता और राजनीतिक दलों का भरोसा बना रहना अनिवार्य है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। आरोपों का अंतिम निर्णय तथ्यों, जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा। विपक्ष ज्ञानेश कुमार की स्थिति को लेकर जो दबाव बना रही है, सत्ता पक्ष के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। उल्टे सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है, देश पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक सुस्ती, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मे बढ़ता टकराव सरकार के विकास कार्यों एवं जरूरी मुद्दों पर समय पर निर्णय नहीं ले पाने के कारण सरकार की परेशानी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इसका असर अंतोगत्वा जनता पर ही पडना है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी-अपनी भूमिका है। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी उन सवालों का जवाब देना है। चुनाव आयोग को भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पारदर्शिता के साथ प्रश्नों का जवाब देने के लिए सामने आना चाहिए। यदि विपक्ष के आरोप गलत हैं, तो तथ्यों के साथ चुनाव आयोग द्वारा उन्हें खारिज किया जाना चाहिए। यदि कहीं गड़बड़ी हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और उसमें सुधार होना चाहिए। चुनाव आयोग को अपनी कार्य प्रणाली इस तरीके से तैयार करनी होगी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को विश्वास हो। पिछले 7 दशकों में राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के बीच जो विश्वास बना था वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लोकतंत्र किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। वह 140 करोड़ देशवासियों का साझा अधिकार और विश्वास है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

1 अप्रैल से खुदरा कारोबार में ई-इनवॉइसिंग की पायलट परियोजना शुरू होगी

नई दिल्ली ।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी पर लगाम लगाने और कर दायरे को व्यापक बनाने के लिए सरकार एक बड़ी पहल करने जा रही है। 1 अप्रैल, 2027 से खुदरा कारोबार में ई-इनवॉइसिंग की पायलट परियोजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत चुनिंदा व्यावसायिक क्षेत्रों के दुकानदारों को ग्राहकों को जारी किए गए बिलों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना होगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य खुदरा लेनदेन की निगरानी बढ़ाना और वास्तविक बिक्री का जीएसटी रिटर्न से मिलान करना है। वर्तमान में कारोबारी केवल कुल बिक्री का ब्योरा देते हैं, लेकिन नई व्यवस्था में कर अधिकारी व्यक्तिगत बिलों के आधार पर बिक्री और कर भुगतान की जांच कर सकेंगे। फिलहाल, सालाना 5 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले व्यवसायों को अन्य कारोबारियों (बी2बी) को जारी बिलों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करना होता है। अब इस व्यवस्था का विस्तार व्यवसाय से उपभोक्ता (बी2सी) लेनदेन तक करने की योजना है। जीएसटी परिषद ने सितंबर 2024 में स्वैच्छिक परीक्षण की सिफारिश की थी, जिसे बाद में कर चोरी वाले क्षेत्रों, जैसे कि रेस्तरां, में अनिवार्य किया जा सकता है। यह कदम कर चोरी पर अंकुश लगाने और राजस्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भूख हड़ताल पर, सरकार और यूनियन आमने-सामने

कनाडा की फर्म को 60 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी बेचने का विरोध

नई दिल्ली ।

आईडीबीआई बैंक के 10,000 से अधिक कर्मचारी 2-3 नवंबर को भूख हड़ताल पर हैं। बैंक के प्रस्तावित निजीकरण और कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बहुलांश हिस्सेदारी बेचे जाने के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज का कहना है कि वर्षों के सार्वजनिक निवेश और कर्मचारियों के योगदान से बैंक अब मुनाफे में है, ऐसे में इसका निजीकरण अनुचित है। यूनियन इस सौदे को देश के एक ऐतिहासिक बैंक का विदेशीकरण बता रही है और जमाकर्ताओं के लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है। उनका तर्क है कि आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाली सरकार एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्तंभ को विदेशी हाथों में क्यों सौंप रही है, जिससे बैंक का प्राथमिक उद्देश्य कॉर्पोरेट मुनाफे में बदल सकता है। वहीं सरकार का तर्क है कि बैंक का सौदा घाटे में नहीं, बल्कि फायदे में हुआ है, जहां फेयरफैक्स ने प्रति शेयर बाजार मूल्य (75.99 रुपए) से अधिक (81 रुपए) बोली लगाई है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (सीसीईए) ने फेयरफैक्स को 60.72 फीसदी हिस्सेदारी (सरकार की 30.48 फीसदी और एलआईसी की 30.24 फीसदी) बेचने की मंजूरी दी है।

कोल इंडिया की रिकॉर्ड कोयला आपूर्ति, पहली बार 7 करोड़ टन का आंकड़ा पार

बिजली क्षेत्र को भी सर्वाधिक कोयला, आयात में भी कमी दर्ज

नई दिल्ली ।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अक्टूबर 2026 में कोयला आपूर्ति के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, पहली बार मासिक आपूर्ति 7 करोड़ टन के आंकड़े को पार कर गई।

यह उपलब्धि देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने और ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों को दर्शाती है, जिससे ऊर्जा संकट की चिंताओं को दूर करने में मदद मिली है। कंपनी ने अक्टूबर 2026 में कुल 7.03 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की, जो पिछले वित्तीय वर्ष के इसी महीने के मुकाबले 19 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि है। इससे पहले का मासिक रिकॉर्ड मार्च 2026 में 6.94 करोड़ टन था। बिजली क्षेत्र को की गई आपूर्ति भी 5.71 करोड़ टन के अब तक के सर्वाधिक मासिक स्तर पर पहुंच गई, जिसने मई 2024 के पिछले रिकॉर्ड को पछाड़ दिया। यह रिकॉर्ड प्रदर्शन ऐसे समय में सामने आया है, जब हाल ही में देश के कई बिजली संयंत्रों में कोयले के कम स्टॉक को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। घरेलू उत्पादन में इस वृद्धि के साथ, अगस्त 2026 में देश का कुल कोयला आयात 5.83 प्रतिशत घटकर 10.457 करोड़ टन रह गया।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 1233, निफ्टी 387 अंक उछला

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार सोमवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दूनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीदारी हावी होने से आई हैं। आज कारोबार के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई, एनटीपीसी, मारुति, बजाज फाइनेंस के शेयरों में उछाल आया जिससे बाजार धारणा मजबूत हुई। सप्ताह के पहले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं आईटी स्टॉक्स में गिरावट रही। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1233.25 अंकों की तेजी के साथ ही 75,692.78 अंकों पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई का निफ्टी 387.70 अंक उछलकर 23,440.80 अंकों पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स की 30 में से 23 कंपनियों के शेयर ही बढ़त पर बंद हुए और शेष सभी 7 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी 50 की 50 में से 38 कंपनियों के शेयर तेजी के साथ बंद हुए और बाकी की सभी 12 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आज सबसे अधिक 11.64 फीसदी की तेजी रही। इसके अलावा टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और एसबीआई के शेयरों में भी तेजी रही।

सेंसेक्स की अन्य कंपनियों की बात करें तो आज टाटा स्टील ,



अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई , एनटीपीसी 2.37, मारुति सुजुकी , बजाज फाइनेंस , एलएंडटी , बीईएल , हिंदुस्तान यूनिलीवर , एशियन पेंट्स , बजाज फिनसर्व , इंडिगो तेजी के साथ बंद हुए। वहीं वहीं दूसरी ओर, आज कोटक महिंद्रा बैंक , आईसीआईसीआई बैंक , सन फार्मा , एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा और टीसीएस के शेयरों में गिरावट रही। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार की तेज शुरुआत हुई।

सुबह सेंसेक्स अपने पिछले बंद भाव 74,459.53 के मुकाबले 75,178.24 पर खुला, जो 718.71 अंकों की शानदार छलांग थी। वहीं निफ्टी ने अपने पिछले बंद भाव 23,053.10 से 169.2 अंक उछलकर 23,222.30 पर सत्र की शुरुआत की

रुपया गिरावट के साथ बंद

मुंबई ।



अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया सोमवार को 9 पैसे की गिरावट के साथ ही 94.86 पर बंद हुआ।

आज सबह शुरुआती कारोबार में रुपया 21 पैसे की गिरावट के साथ ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.97 पर पहुंच गया। विदेशी बाजारों में अमेरिकी डॉलर की बढ़ती मांग से घरेलू मुद्रा पर दबाव है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि हालांकि घरेलू बाजारों में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी से रुपये को निचले स्तर पर थोड़ा समर्थन मिला।

वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.90 प्रति डॉलर पर खुला। फिर फिसलकर 94.97 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 21 पैसे की गिरावट है। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.76 पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.07 फीसदी की बढ़त के साथ 109.95 पर पहुंच गया।

ईएएए इंडिया अल्टरनेटिव्स के शेयर एक प्रतिशत चढ़कर सूचीबद्ध

नई दिल्ली ।



एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज की अनुषंगी कंपनी ईएएए इंडिया अल्टरनेटिव्स लिमिटेड का शेयर अपने निर्गम मूल्य 1,665 रुपये से करीब एक प्रतिशत की बढ़त के साथ सोमवार को बाजार में सूचीबद्ध हुआ। बीएसई पर शेयर ने 1,673 रुपये पर कारोबार शुरू किया जो निर्गम मूल्य से 0.48 प्रतिशत अधिक है। एनएसई पर शेयर निर्गम मूल्य से 0.63 प्रतिशत अधिक 1,675.50 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। बाद में बीएसई पर शेयर 1.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,685.35 रुपये पर और एनएसई पर 1.57 प्रतिशत चढ़कर 1,691.70 रुपये पर कारोबार करने लगा। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 10,900.87 करोड़ रुपये रहा। ईएएए इंडिया अल्टरनेटिव्स लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को पिछले सप्ताह बुधवार को बोली के अंतिम दिन 5.25 गुना अभिदान मिला था। आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 1,585-1,665 रुपये प्रति शेयर था।वर्ष 2008 में स्थापित ईएएए इंडिया अल्टरनेटिव्स एक वैकल्पिक निवेश मंच है जो बुनियादी ढांचे, वाणिज्यिक रियल एस्टेट तथा निजी ऋण सहित विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में दीर्घकालिक पूंजी का प्रबंधन करता है।

कंपनियों पर बढ़ा बोझ, बिक्री का 44 फीसदी हिस्सा खर्च में गया

पिछले वर्ष में दर्ज 38.77 प्रतिशत के आंकड़े से 5.72 प्रतिशत अधिक

नई दिल्ली ।

भारतीय कंपनियों को कच्चे माल की बढ़ती लागत से जूझना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर उनके मुनाफे और अंततः उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि जून तिमाही में देश की गैर-वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों की प्रत्येक 100 रुपये की बिक्री में से 44 रुपये कच्चे माल और संबंधित खर्चों को पूरा करने में चले गए। यह पिछले लगभग एक दशक में किसी भी तिमाही में दर्ज किया गया सबसे ऊंचा आंकड़ा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ती लागत के दबाव को दर्शाता है। सीएमआईई द्वारा समीक्षा की गई 3,687 गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए जून तिमाही में कच्चे माल, स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स पर खर्च का हिस्सा 44.49 प्रतिशत रहा। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 38.77 प्रतिशत के आंकड़े से 5.72 प्रतिशत अधिक है। स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स में विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उपयोग होने वाली सहायक वस्तुएं, जैसे लुब्रिकेंट्स या कलपुर्जे शामिल हैं। यह रुझान सितंबर तिमाही में भी बरकरार रहा, जहां कच्चे माल और उससे जुड़ी लागत कुल बिक्री का लगभग 41 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (39.8 प्रतिशत) से अधिक है। गैर-वित्तीय क्षेत्र में स्टील, ऑटोमोबाइल, खनन और निर्माण जैसी प्रमुख औद्योगिक कंपनियां शामिल हैं। यह तीसरी तिमाही है जिस पर फरवरी में शुरू हुए पश्चिम एशिया संघर्ष का असर पड़ा है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई हैं और कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि कंपनियों के पास आमतौर पर कच्चे माल का स्टॉक होता है जो अस्थायी लागत बढ़ोतरी से बचाव कर सकता है, लेकिन यह सुरक्षा सीमित समय के लिए ही होती है। जून के ये उच्च आंकड़े चालू सितंबर तिमाही के आय सत्र के लिए संभावित चुनौतियों का संकेत देते हैं। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार कच्चे माल की बढ़ती लागत कुछ खास क्षेत्रों में मांग को प्रभावित कर सकती है, खासकर उन घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर जो कीमतें नहीं बढ़ा पाई हैं। हालांकि, केबल और सीमेंट कंपनियों जैसे कई अन्य क्षेत्रों ने इस लागत दबाव का बेहतर तरीके से मुकाबला किया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) जैसे सेवा उद्योगों और फार्मास्युटिकल्स जैसे क्षेत्रों पर सबसे कम असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इनमें कच्चे माल की लागत बिक्री का एक छोटा हिस्सा होती है।

अक्टूबर में धीमी पड़ी विनिर्माण की रफ्तार

विनिर्माण पीएमआई 55.1 से घटकर 54.7 पर

नई दिल्ली ।

अक्टूबर में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों की रफ्तार में मामूली कमी दर्ज की गई है। एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) सितंबर के 55.1 से घटकर अक्टूबर में 54.7 पर आ गया। हालांकि, 50 के विस्तार स्तर से काफी ऊपर रहने के कारण यह अब भी मजबूत विस्तार का संकेत देता है, जिसकी मुख्य वजह उत्पादन और नए ऑर्डर में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि थी। मासिक सर्वेक्षण के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन और नए ऑर्डर में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि देखी गई। हालांकि, लागत का दबाव मध्यम रहने से गतिविधियों की रफ्तार धीमी होने का असर सीमित रहा। पीएमआई का 50 से ऊपर रहना विस्तार को दर्शाता है, और 54.7 का आंकड़ा दीर्घकालिक औसत से ऊपर तथा मजबूत विस्तार की स्थिति में है। सर्वेक्षण बताता है कि नए ऑर्डर और उत्पादन वृद्धि की गति धीमी हुई, पर मांग में सुधार जारी रहा। नए निर्यात ऑर्डर छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचना एक सकारात्मक संकेत रहा, जिसने उत्पादन को सहारा दिया। कंपनियों ने अस्थिर वैश्विक माहौल और बढ़ती उत्पादन जरूरतों के



मद्देनजर कच्चे माल का भंडार आठ महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। एचएसबीसी की एक अर्थशास्त्री ने इस गिरावट के बावजूद इसे मजबूत विस्तार के दायरे में बताया। रोजगार के मोर्चे पर, विनिर्माण क्षेत्र में लगातार दूसरे महीने नियुक्तियां बढ़ीं, हालांकि उनकी रफ्तार धीमी रही। वहीं मांग बढ़ने के बावजूद कारोबारी विश्वास कमजोर हुआ और दीर्घकालिक औसत से नीचे बना रहा, जो भविष्य की अनिश्चितताओं को दर्शाता है।

बजाज ऑटो की बिक्री 14 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली ।

बजाज ऑटो की अक्टूबर में कुल बिक्री सालाना आधार पर 14 प्रतिशत बढ़ी। दोपहिया और वाणिज्यिक वाहन दोनों खंडों में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। वाहन विमान विनिर्माता कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया कि उसकी कुल थोक बिक्री 5,91,876 इकाई रही, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 5,18,170 इकाई थी। घरेलू बिक्री 12 प्रतिशत बढ़कर 3,51,148 इकाई हो गई जबकि निर्यात 18 प्रतिशत बढ़कर 2,40,728 इकाई रहा। कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री 13 प्रतिशत बढ़कर 5,01,194 इकाई हो गई जो एक साल पहले की समान अवधि में 4,42,316 इकाई थी। कुल वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 20 प्रतिशत बढ़कर 90,682 इकाई रही, जबकि एक साल पहले यह 75,854 इकाई थी। बजाज ऑटो की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान कुल बिक्री 22 प्रतिशत बढ़कर 35,79,011 इकाई हो गई।दोपहिया वाहनों की बिक्री 22 प्रतिशत बढ़कर 30,07,707 इकाई रही, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 23 प्रतिशत बढ़कर 5,71,304 इकाई हो गई।

भारत-यूरोपीय संघ ने एफटीए को लागू करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की

वाणिज्य सचिव ने ब्रसेल्स में की मुलाकात, व्यापार सुगमता और हीरा उद्योग पर भी बात

नई दिल्ली ।

भारत और यूरोपीय संघ ने इस साल दिसंबर में प्रस्तावित अपने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण चर्चाएं कीं। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पिछले सप्ताह ब्रसेल्स की अपनी यात्रा के दौरान इन मुद्दों पर बातचीत की। अग्रवाल ने यूरोपीय आयोग के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी व कराधान महानिदेशालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। चर्चा में सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार सुगमता और एफटीए कार्यान्वयन की तैयारियां प्रमुख रहीं। दोनों पक्षों ने व्यवसायों के समर्थन, लेनदेन लागत में कमी और सुचारु वैध व्यापार हेतु कुशल, पारदर्शी व डिजिटल सीमा शुल्क प्रक्रियाओं की अहमियत पर जोर दिया।

27 जनवरी को संपन्न हुआ यह एफटीए भारत के चमड़ा, कपड़ा, रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। एफटीए के अलावा, सचिव अग्रवाल एंटवर्प के हीरा उद्योग हितधारकों से भी मिले, जो हीरा राजधानी कहलाता है। यहां वैश्विक हीरा मूल्य श्रृंखला, प्रमाणन, जिम्मेदार खरीद और भारत के बढ़ते हीरा बाजार के अवसरों पर चर्चा हुई।

हवाई अड्डा शुल्क में कटौती से भारतीय बाजार का बढ़ेगा विस्तार-इंडिगो के सीईओ

नई दिल्ली ।

देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विली वॉल्श ने भारत में हवाई अड्डों के उच्च शुल्कों और करों में कटौती की पुरजोर वकालत की है। सोमवार को दिल्ली में उन्होंने स्पष्ट किया कि विमानन क्षेत्र में व्यापक विस्तार के लिए यह आवश्यक है और हवाई अड्डों की एकाधिकार स्थिति के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारित करने की जरूरत है। वॉल्श ने कहा, हवाई अड्डों के शुल्क बहुत अधिक हैं और अगर हमारे यहां कर कम होते, तो यह बाजार कहीं बेहतर प्रदर्शन करता। इसलिए कम कर और कम हवाई अड्डा शुल्क ही आगे बढ़ने का रास्ता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में विस्तार के अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए सभी संबंधित पक्षों को अपनी लागत पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

इंडिगो जो 65 प्रतिशत से अधिक घरेलू बाजार हिस्सेदारी के साथ देश की अग्रणी विमानन कंपनी है और प्रतिदिन लगभग 2,200 उड़ानें संचालित करती है, हमेशा हवाई अड्डों से बेहतर मूल्य की अपेक्षा करती है। वॉल्श ने याद दिलाया कि वैश्विक एयरलाइन संगठन आईएटीए के महानिदेशक के रूप में भी उन्होंने भारत में हवाई अड्डों के शुल्कों और करों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, और उनके विचार अब भी अपरिवर्तित हैं।

इंडिया ब्लॉक की रैली से दिल्ली के कारोबारियों को 10 हजार करोड़ का नुकसान

पुरानी और सेंट्रल दिल्ली के 20-25 बाजार हुए प्रभावित, आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर



नई दिल्ली ।

दिवाली से पहले बाजारों में रौनक की उम्मीदों को 1 नवंबर को हुई इंडिया ब्लॉक की रामलीला मैदान रैली से गहरा झटका लगा है। व्यापारी संगठन सीटीआई ने दावा किया है कि इस रैली के चलते पुरानी और सेंट्रल दिल्ली के करीब 20 से 25 बाजारों में कारोबार ठप रहा, जिससे व्यापारियों को लगभग 10,000 से 11,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। सीटीआई के एक अे धिकारी के मुताबिक, रामलीला मैदान के आसपास की करीब 3 लाख दुकानों में से लगभग 80 फीसदी यानी 2.5 लाख दुकानें रैली के दिन बंद रहीं। व्यापारियों ने बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों की आवाजाही की आशंका के चलते दुकानें बंद रखने का फैसला किया, जिससे ग्राहक भी कम आए। चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, कश्मीरी गेट, चावड़ी बाजार, दरियागंज, पहाड़गंज, कनॉट प्लेस सहित कई थोक और खुदरा बाजार पूरी तरह प्रभावित हुए। इन बाजारों से सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी सामान की आपूर्ति होती है। सीटीआई का दावा है कि रोजाना करीब 5,000 ट्रक और टेम्पो की आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे त्योहारों से पहले आपूर्ति श्रृंखला में बड़ा व्यवधान आया।

नवंबर में निवेश के दो नए द्वार, डेट फंड से चांदी ईटीएफ तक

न्यूनतम 5,000 रुपये से कर सकेंगे शुरुआत

नई दिल्ली ।



म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नवंबर का पहला हफ्ता नए अवसरों से भरा है। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड और क्वांट म्यूचुअल फंड दो नए फंड ऑफर (एनएफओ) लॉन्च करने जा रहे हैं, जो निवेशकों को डेट और चांदी में निवेश के विकल्प मुहैया कराएंगे। ये स्कीमें अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल और निवेश लक्ष्यों वाले निवेशकों को आकर्षित करेंगी। कोटक फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान सीरीज 336 कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड 2 से 4 नवंबर तक कोटक फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान सीरीज 336 खोलेगा। यह एक क्लोज्ड-एंड डेट स्कीम है, जिसकी अवधि 125 दिन होगी। यह स्कीम सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड सहित डेट व मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगी। इसमें न्यूनतम 5,000 रुपये से निवेश किया जा सकता है और कोई एंट्री या एग्जिट लोड नहीं है। रिस्कोमीटर पर इसे मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, जो शॉर्ट-टर्म के लिए डेट में सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए उपयुक्त है। वहीं क्वांट म्यूचुअल फंड 4 से 6 नवंबर तक क्वांट सिल्वर ईटीएफ एफओएफ लॉन्च करेगा। यह एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड्स है, जो क्वांट सिल्वर ईटीएफ की यूनिट्स में निवेश करके चांदी की कीमतों का फायदा उठाने का लक्ष्य रखता है।

इसमें भी न्यूनतम 5,000 रुपये से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन अगर निवेशक यूनिट आवंटन के 15 दिनों के भीतर निकासी करते हैं, तो एक फीसदी एग्जिट लोड लगेगा। इस स्कीम को बहुत अधिक जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है, जो लंबी अवधि के लिए चांदी में निवेश करने और कीमतों में उतार-चढ़ाव सहन करने वाले निवेशकों के लिए है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1



बचे हुए खाने को कभी न करें बर्बाद ! अपनाएं ये स्मार्ट किचन हैक्स

ताजा खाना खाने से सेहत भी बढ़िया होती है। लेकिन घर में हर बार नाप-तौल के खाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बचे हुए खाने को कभी भी बर्बाद न करें, इससे अच्छा है कि लेफ्टओवर का फूड यूज कर सकते हैं। जब आपका खाना बनाने का मन न करें तो इन आसान तरीकों से लेफ्टओवर फूड को का इस्तेमाल कर सकते हैं।

लेफ्टओवर की करें प्लानिंग

कई बार होता है कि बाहर किसी काम से हमें कहीं जाना होता है, तो फिर घर लौटकर खाना बनाने में दिक्कत होती है। ऐसे में आप अपनी मनपसंद रेसिपी ज्यादा मात्रा में तैयार करके रख लें। फिर इसे फ्रिज में स्टोर करके रख दें, अब आपको खाना पकाने की कोई चिंता नहीं होगी। आप चाहे तो चीला या डोसा के लिए ज्यादा बैटर बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं या फिर बिना सिकी हुई पैटी या उबले आलू।

ये चीजें लगती हैं ज्यादा टेस्टी

रात या दोपहर का खाना बच ही जाता है, ऐसे में आप अगली मील की प्लानिंग में बचे हुए खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीजें दोबारा गर्म करके खाने और पीने में ज्यादा टेस्टी लगती है, जैसे कि सूप, दाल, करी, रोस्ट की गई सब्जियां।

पारदर्शी कंटेनर में स्टोर करें

अक्सर होता है कि हम सभी खाना फ्रिज में रखकर भूल जाते है। इसलिए हमेशा कांच के पारदर्शी लंच बॉक्स या मैसन जार में खाना स्टोर करें। यह आपको फ्रिज खोलते ही नजर आने लगेंगे।

बचे हुए खाना से नई रेसिपी बनाएं

अगर आपका खाना बच जाता है, तो आप अगले मील के लिए इसे खा सकते हैं। कुछ रेसिपी बनाकर बचा हुआ खाना बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, बची हुई सब्जियों को ऑमलेट या फिर चीले में इस्तेमाल करें। सलाद में उबले हुए काबुली चना डाल दें। बचे हुए चावल से फ्राइड राइस या फिर एग राइस बना सकते हैं। इसके अलावा, आप लेफ्टओवर फूड को नए रुप में सर्व करके डिशेज बना सकते हैं। इस तरह से आप बचा हुआ खाने को खत्म कर सकते हैं।

गुड़ की चाय फटने की टेंशन खत्म ! आजमाएं ये सीक्रेट टिप्स, बनेगी लाजवाब



चाय लवर हर मौसम में इसे स्वाद से पीते हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी चाय की लत वाले इसे खूब पीते है। चाय के दीवाने चिलचिलाती धूप में बड़े चाव से चाय पीने के शौकीन होते है। इस मौसम में या फिर सर्दियों के दौरान गुड़ की चाय पीने का एक अलग ही मजा होता है। यह स्वाद के साथ ही काफी हेल्दी होती है। लेकिन कई बार गुड़ की चाय बनाने के फट जाती है। अगर आप इसे सही तरीके से बनाएंगे तो यह कभी नहीं फटेगी। आइए आपको बताते हैं किन तरीकों से बनाएं गुड़ की टी।

सही समय पर दूध डलना जरुरी

कई लोग गुड़ की चाय बनाते समय बड़ी गलती यह करते हैं कि गुड़ के साथ ही तुरंत दूध डाल देते हैं। गुड़ को चाय के पानी में घोलते ही दूध डालें। पहले चाय के पानी में गुड़ को अच्छे से घुलने दें और इसे एक-दो उबाल आने दें। फिर गैस बंद कर दें या आंच को धीमी कर दें। चाय का तापमान कम होने बाद ही दूध को डालें।

पहले दूध को गर्म करें

अगर आप ठंडा या सामान्य तापमान का दूध उबलते हुए गुड़ वाले पानी में डल रहे, तो यह आपके चाय को फाड़ देगी। इसलिए आप दूसरे बर्नर पर दूध को गर्म करके डाल दें। इसके बाद आप गुड़ वाला घोल तैयार होने के बाद इसमें गर्म दूध को धीरे-धीरे मिश्रण में डाले। इसके अलावा, नकली गुड़ से बचें, इनमें केमिकल भरा होता है। इसलिए आप भूरा या काले रंग वाल गुड़ खरीदें। जिससे चाय अच्छी बनेंगी।

कैसे बनाएं गुड़ वाली चाय

» इसके लिए एक पैन में पानी लें और उसमें अदरक, इलायची या अन्य मसाले कूटकर डाल दीजिए।

» जब पानी उबलने लगे, तो बारीक कटा हुआ गुड़ डालें और उसे पूरी तरह से घुलने दें।

» इसके बाद आप गुड़ चाय पत्ती डालें और चाय को अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक उबलने दें, ताकि मसाला और गुड़ का स्वाद पानी में पूरी तरह आ जाए।

» चाय का बेस जब कड़क हो जाए, तो गैस बंद कर दें या आंच बिल्कुल धीमी कर दें।

» इसके बाद आप दूसरे पैन में गर्म किया हुआ उबला हुआ दूध इस गुड़ वाले मिश्रण में धीरे-धीरे मिलाएं।

» इस मिश्रण को एक बार फिर हल्का सा आंच पर रखें और सिर्फ एक उबाल आने दें। उबाल आते ही तुरंत गैस बंद चाय को छान लें।



खाना खाते समय हम सभी उसके टेस्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर अपने खाने को तीखा या चटपटा बनाने के लिए अधिक मसालों का इस्तेमाल करते हैं। कभी-कभी तीखी चटनी या मिर्च का अचार खाने के स्वाद को बढ़ा देता है। इससे आपके टेस्ट बड को तो मजा आता है, लेकिन स्किन पर इसका उल्टा असर हो सकता है। बहुत ज्यादा तीखा खाने से चेहरे में रेडनेस व डलनेस की शिकायत होती है। वो गर्मी जो शरीर में महसूस होती है, स्किन पर भी असर डालती है, जिससे ऑयल ज्यादा बनने लगता है और चेहरा डिहाइड्रेट हो जाता है।

मसालेदार खाना खाकर चेहरा दिखने लगा है डल, तो इन आसान घरेलू नुस्खों से मिनटों में पाएं दमकती स्किन

ऐसे में अधिकतर लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने पसंदीदा मसालेदार खाने से दूरी बनानी पड़ेगी। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने पसंदीदा खाने का लुत्फ उठाते हुए भी ग्लोइंग स्किन पा सकती हैं। बस जरूरत है कुछ आसान स्किनकेयर स्टेप्स अपनाने की। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ आसान तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जो मसालेदार खाने के बाद चेहरे की डलनेस को दूर करने में मदद करेंगे-

भरपूर पानी पीएं

अगर आप अपनी स्किन के खोए हुए ग्लो को वापिस पाना चाहती हैं तो ऐसे में आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। दरअसल, मसालेदार खाना खाने से शरीर में पसीना और गर्मी बढ़ जाती है, जिससे शरीर का पानी कम होने लगता है। इसी डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन रूखी, डल और बेजान नजर आने लगती है। इसलिए दिनभर में भरपूर पानी पीएं। इसके अलावा, नारियल पानी पीना भी काफी अच्छा रहता है। नारियल पानी से हाइड्रेशन के साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलते हैं, जिससे स्किन की नमी भीतर से बनी रहती है।

लगाएं कूलिंग फेस मास्क

मसालेदार खाने के बाद स्किन को सुकून और नमी की जरूरत होती है। इसलिए, आपको एलोवेरा, खीरा या दही से बने मास्क को स्किन पर अप्लाई करना चाहिए। यह स्किन को ठंडक देने के साथ-साथ जलन कम करता है। मास्क बनाने के लिए आप दो चम्मच दही के साथ एक चम्मच एलोवेरा जेल और कुछ बूंदे गुलाबजल मिक्स करके अप्लाई करें। करीबन 15-20 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरो धो लें। इससे स्किन को ठंडक, नमी व ग्लो मिलता है।

हाइड्रेटिंग टोनर या गुलाबजल से करें स्प्रे

मसालेदार खाने से शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। गर्मी बढ़ने से स्किन की नमी जल्दी उड़ जाती है। ऐसे में गुलाबजल या टोनर लगाने से फायदा मिलता है। इससे चेहरा तुरंत ठंडा और फ्रेश लगता है, साथ ही पीएच बैलेंस भी बना रहता है। इसलिए, दिनभर में 2-3 बार गुलाबजल स्प्रे करें। इससे स्किन की नमी बनी रहती है। साथ ही, वह फ्रेश महसूस होती है।

फूड क्रेविंग्स से हेल्थ को हो सकता है नुकसान, इसे रीसेट करने के लिए आजमाएं ये आसान ट्रिक्स

हम सभी को अक्सर फूड क्रेविंग्स होती ही हैं। कभी-कभी कुछ मीठा खाने का मन होता है तो कभी हम कुछ चटपटा खाते हैं। जब यह क्रेविंग्स होती हैं तो हम खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। अचानक से मन करता है कि अभी चॉकलेट चाहिए, बस अभी! ऐसे में अक्सर हम अपना फ्रिज टटोलने लग जाते हैं या फिर बाहर अपना पसंदीदा फूड खाने के लिए निकल जाते हैं। हो सकता है कि आप भी अपने टेस्ट बड अैर फूड क्रेविंग्स की वजह से परेशान हो और इससे आपकी सेहत को लगातार नुकसान हो रहा हो। हालांकि, ऐसे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी फूड क्रेविंग्स को आसानी से रीसेट कर सकती हैं। बस आपको अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है और कुछ छोटी-छोटी आदतों को अपाने की जरूरत है। जब आप ऐसा करते हैं तो क्रेविंग्स आप पर हावी नहीं हो पाएंगी। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही आसान तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप फूड क्रेविंग्स को आसानी से रीसेट कर सकते हैं-

पहले पीएं पानी - अगर आपको फूड क्रेविंग्स हो रही हैं, तो ऐसे में कुछ भी खाने से पहले एक पूरा गिलास पानी पियो और फिर 10 मिनट के लिए रुक जाओ। इससे कई बार आपकी क्रेविंग्स खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि कई बार शरीर की प्यास को दिमाग भूख समझ लेता है। पानी पीने से शरीर हाइड्रेट होता है, झूठी भूख की फीलिंग कम होती है और आप बेवजह की स्नैकिंग से बच पाते हैं।

नींद के साथ समझौता नहीं - अक्सर लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं और इससे भी उनकी फूड क्रेविंग्स बढ़ने लगती हैं। दरअसल, कम नींद लेने से घ्रेलिन हार्मोन बढ़ता है और लेप्टिन हार्मोन घटता है। यही असंतुलन जंक फूड की क्रेविंग बढ़ाता है, खासकर कार्ब्स और मिठाइयों की क्रेविंग्स कई गुना बढ़ने लगती है। इसलिए रोजाना 7-8 घंटे की गहरी अवश्य लें।

करें माइंडफुल ईटिंग - अगर आप बेवजह की फूड क्रेविंग्स से बचना चाहती हैं तो ऐसे में माइंडफुल ईटिंग करना यकीनन काफी अच्छा रहता है। आप हमेशा धीरे-धीरे खाएं और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खाना खाएं। दरअसल, जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो ऐसे में दिमाग को समझ आता है कि पेट भर गया है। जल्दी-जल्दी खाने से ये सिग्नल कन्फ्यूज हो जाते हैं और बाद में दोबारा कुछ खाने का मन करता है, भले ही पेट भरा हो।





पाचन शक्ति बढ़ाएगा भुना जीरा या जीरा पानी ? जानें कौन है सबसे बेहतर उपाय !

खराब जीवनशैली और गलत खानपान के कारण कई बीमारियां शरीर को घेर लेती है। आजकल लोग मोटापे से काफी परेशान हैं। वहीं, कुछ लोगों का डाइजेशन खराब रहता है। पेट भारी होने से उन्हें कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। पेट की पाचन क्रिया जबरदस्त रहती है तो शरीर भी हेल्दी रहता है। खाना खाने के बाद भोजन पच नहीं रहा, तो एसिडिटी, गैस और पेट दर्द जैसी परेशानियां होने लगती है। अब आपको जानना बेहद जरुरी है कि भुना जीरा या जीरे का पानी कौन है सबसे बेहतर। आइए आपको बताते हैं-

भुना जीरा के फायदे

- ये डाइजेशन एंजाइम्स को एक्टिव करता है। यह खाना को जल्दी और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है।

- भुना हुआ जीरा खाने से गैस और पेट फूलने की समस्या दूर हो जाती है।

- भुना हुआ जीरा सेवन करने से शरीर को ज्यादा पोषण मिलता हैं।

- इसमें पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट्स आंतों की सूजन कम करते हैं।

कैसे सेवन करें

भुना जीरा को आप अपने खाने में डाल सकती है। इसको आप सलाद, रायता, दही या सब्जी में मिलाकर सेवन कर सकती हैं।

जीरा पानी के फायदे

- जीरा पानी पीने से पेट के एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे खाना आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है।

- जीरा पानी पीने से एसिडिटी और जलन से भी राहत मिलती है।

- ये पानी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है।

कैसे सेवन करें

आपको सुबह खाली पेट गुनगुना जीरा पानी पीना सबसे बेहतरीन माना जाता है। यह आपके पाचन को बेहतर करता है।

कौन बेहतर है- भुना जीरा या जीरा पानी

अगर आपक हल्की-फुल्की गैस है, तो भुना जीरा का सेवन कर सकते हैं। यदि आपको बार-बार एसिडिटी, कब्ज और पेट फूलने की समस्या हो रही है, तो आपको जीरा पानी का सेवन करना चाहिए। दोनों ही अपने तरीके से फायदेमंद है। आप जैसा चाहे इसका सेवन करें।

हील्स पहनकर पैरों में होता है भयंकर दर्द ? इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से पाएं तुरंत आराम !

लड़कियां स्टाइलिंग और फैशन के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं करती। स्टाइलिश बनाने के लिए कभी-कभी लड़किया दर्द सहने को भी तैयार रहती हैं। ऑफिस, पार्टी और शादी में आउटफिट लुक को परफेक्ट बनाने के लिए महिलाएं हील्स जरुर पहनती है। हील्स पहनना सभी को पसंद है और यह लुक भी गजब का देता है। लंबे समय तक हील्स पहनने से पैरों में दर्द या फिर टखनों में जकड़न की शिकायत होने लगती है। कई बार तो दर्द इतना भंयकर होता है कि चलना-फिरना भी मुश्किल हो जाता है। आइए आपको बताते हैं कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में, जो हील्स पहनने में काफी फायदेमंद रहेगी।

कफ स्ट्रेच - आमतौर पर हील्स पहनने पर पिंडलियों में टाइटनेस आ जाती है। कफ स्ट्रेच करने से उस मसल्स की टाइटनेस को कम करने में मदद करता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आप चाहे तो वॉल के पास खड़े होकर काफ स्ट्रेच कर सकते हैं। इसे करने के लिए दीवार के सामने सीधे खड़े हो जाएं। अब एक पैर आगे और दूसरा पीछे रखें। पीछे वाला पैर एड़ी के साथ जमीन पर टिका रहे। दोनों हाथ दीवार पर रखकर थोड़ा आगे झुके, जब तक पीछे वाले पैर की पिंडली में खिंचाव न महसूस हो। इसे करीब 20-30 सेकंड ऐसे ही रुको। अब दूसरे पैर से भी इसी तरह स्ट्रेच करें।

फुट आर्च स्ट्रेच -इसे करते समय टॉवल या रेसिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। हील्स पहनने से जो मसल्स टाइट हो जाती है, उन्हें ये स्ट्रेच खोलता है। इसे करने के लिए एक टॉवल या रेसिस्टेंस बैंड लो। इसे अपने पैरों के पंजे में फंसाएं और धीरे-धीरे अपनी तरफ खींचो। ऐसा करने से पैरों के आर्च और एड़ी खिंचाव फील होगा। अपने क्षमतानुसार इसी पोजिशन में रुकें और सामान्य अवस्था में लौट आएं।

एंकल रोल्स -एंकल रोल्स स्ट्रेच को आप कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। यह आपके एंकल ज्वॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बना देता है और पैर की सूजन भी कम हो जाती है। इसे करने के लिए सबसे पहले आप कुर्सी पर बैठ जाएं। अब एक पैर ऊपर उठाओ और एंकल को पहले घड़ी की दिशा



में, फिर उल्टी दिशा में घुमाओ। ऐसे ही दूसरे पैर से भी करें। इस तरह आप दोनो डायरेक्शन में 10-10 बार रोल करें।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

ईरान समझौता करना चाहता है, बातचीत सही दिशा में, सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला : ट्रंप

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ ईरान समझौता करना चाहता है और दोनों देशों के बीच बातचीत अच्छी चल रही है। हालांकि, उन्होंने ईरान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह समझौता करने के बाद पीछे हट जाता है। फ्लोरिडा में हैलोवीन पार्टी के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन यह देखना होगा कि क्या वह वास्तव में किसी समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, ''वे समझौता करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि वे ऐसा कर पाते हैं या नहीं।'' ट्रंप ने कहा कि ईरान बहुत भरोसेमंद नहीं है। वह पहले समझौता करता है और फिर उससे पीछे हट जाता है। इसके बावजूद अमेरिका बातचीत को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने कतर की मध्यस्थता में चल रही बातचीत की समयसीमा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि अमेरिका को कोई खास जल्दबाजी नहीं है। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि 'अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में ईरान की नौसेना, वायुसेना और हथियार निर्माण की क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाया गया है।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े 'पिकएक्स माउंटेन' को निशाना बनाने की धमकी भी दोहराई। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहे तो इस ठिकाने पर बहुत तेजी से हमला कर सकता है। अमेरिका का दावा है कि इस पहाड़ी के नीचे ईरान का परमाणु ठिकाना मौजूद है। ईरान पर दोबारा सैन्य हमले का आदेश देने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने सवाल को 'बेवकूफाना' बताया। उन्होंने कहा, ''मान लीजिए कि मैंने ऐसा करने का फैसला किया, तो क्या मैं आपको पहले बता दूंगा? मैं यह नहीं बता सकता।

घड़ी के शीशे बनाने वाली झोउ छुनफेई अब चीन की सबसे अमीर महिला बनीं

बीजिंग, एजेंसी। चीन की एक महिला ने फैक्टरी में काम करने से लेकर देश की सबसे अमीर महिला बनने तक का सफर तय किया है। 56 साल की झोउ छुनफेई ने किशोरावस्था में ही स्कूल छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने एक फैक्टरी में काम शुरू किया। आज वह ग्लास बनाने वाली कंपनी लेंस टेक्नोलॉजी की संस्थापक हैं। उनकी अनुमानित संपत्ति 1.27 लाख करोड़ युआन यानी करीब 1.80 लाख करोड़ रुपये है। 28 अक्तूबर को जारी हुरुन की 2026 की चीन की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में झोउ ने फिर पहला स्थान हासिल किया है। पिछले एक साल में उनकी संपत्ति 15% बढ़ी है। एपल के आईफोन से बदली किस्मत झोउ को बड़ी कामयाबी 2007 में मिली, जब उसे एपल के शुरुआती आईफोन के लिए ग्लास कवर बनाने का ऑर्डर मिला। इसके बाद एपल का कारोबार लेंस की कमाई का बड़ा स्रोत बन गया। हुरुन एक वैश्विक शोध और प्रकाशन संस्थान है, जो 1999 से चीन की सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी कर रहा है। यह सूची चीन के सबसे अमीर लोगों की समग्र सूची से अलग है। इसमें परिवारों या दंपतियों की संयुक्त संपत्ति के बजाय महिलाओं की व्यक्तिगत संपत्ति का आकलन किया जाता है, जिसे परिवार की संपत्ति से अलग पहचाना जा सके।

समुद्र में 352किलोमीटर की गहराई पर केंद्र; सुनामी का अलर्ट नहीं

टोक्यो, एजेंसी। जापान के मी प्रांत के तट के पास रविवार सुबह 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक, भूकंप का केंद्र भूकंप का केंद्र मी प्रांत की राजधानी त्सु से करीब 110 किलोमीटर दक्षिण में था। त्सु की आबादी 2.5 लाख से ज्यादा है। भूकंप समुद्र में जमीन से 352 किलोमीटर की गहराई में आया। भूकंप के बाद सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। फिलहाल किसी के घायल होने या जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर की वेबसाइट पर लोगों ने बताया कि झटके काफी देर तक महसूस हुए। शुरुआत में हल्के झटके लगे, जो धीरे-धीरे तेज होते गए। जापान दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। यह चार बड़े टेक्टोनिक प्लेटों पर बसा है और प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' का हिस्सा है। हर साल यहां करीब 1500 भूकंप आते हैं, जिनमें से ज्यादातर हल्के होते हैं। जापान के नोटो द्वीप में 2024 में आए भूकंप में करीब 600 लोग मारे गए थे। 2011 में 9.0 तीव्रता के भूकंप और सुनामी ने 18 हजार से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी।

इजराइल में बहुमत के दूर नेतन्याहू, अरब पार्टियां बनेंगी किंगमेकर !

वाशिंगटन, एजेंसी। इजराइल के संसदीय चुनाव का नतीजा स्पष्ट नहीं रहा है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाला दक्षिणपंथी गुट (लिकुड के नेतृत्व में) सबसे बड़ा राजनीतिक समूह बनकर उभरा है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से पीछे रह गया है. अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों के अच्छे प्रदर्शन ने राजनीतिक समीकरण को और उलझा दिया है. इससे देश की सत्ता किसके हाथ में होगी, यह तय करने में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है.

28 अक्टूबर को आई ताजा रिपोर्टों से चुनाव के मुख्य विरोधाभास की तस्वीर और साफ हो गई है. लगभग 92 प्रतिशत वोटों की गिनती के बाद, द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू के गुट को 53 सीटें, यहूदी विपक्षी गुट को 48 सीटें और अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों को 19 सीटें मिलने का अनुमान है. नेतन्याहू बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों के आंकड़े से 8 सीटें पीछे रह जाएंगे. वहीं, अगर अरब-नेतृत्व वाली पार्टियां विपक्ष का समर्थन करती हैं, तो विपक्ष 67 सीटों तक पहुंच सकता है. इस गणित की वजह से बातचीत में अरब-नेतृत्व वाली पार्टियां अहम हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विपक्ष की सरकार बन ही जाएगी. चुनाव प्रचार के दौरान, यहूदी विपक्ष के कई नेताओं ने अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करने का विरोध किया था, जबकि नेतन्याहू ने भी उनके समर्थन पर निर्भर रहने से इनकार कर दिया है.



जॉइंट लिस्ट जो इजराइल में अरब-बहुसंख्यक राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है, 2015 के चुनाव से पहले हदाश, बलाद, राआम और ताल ने मिलकर बनाया था. इसके बावजूद, इस गठबंधन ने नेतन्याहू को सत्ता से हटाने में मदद करने की इच्छा जताई है. इससे आइसेनकोट पर यह तय करने का दबाव बढ़ गया है कि क्या उन्हें उन पार्टियों के साथ बातचीत करनी चाहिए, जिनकी राष्ट्रीय पहचान और फिलिस्तीनी मुद्दे पर उनसे बिल्कुल अलग राय है. इजराइल के लिए इन चुनावों के क्या मायने हैं - इन चुनावों ने नेतन्याहू के इस दावे को कमजोर कर दिया है कि उनकी सरकार अपने आप बनी रहेगी, भले ही लिकुड अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है. उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे विपक्ष को अपनी संसदीय ताकत और अरब पार्टियों के समर्थन को एक साथ लाने से रोकें. यह फर्क समझना जरूरी है. नेतन्याहू अपने राजनीतिक करियर में कई संकटों से उबर चुके हैं. इससे पहले भी उनके विरोधी, जनता की नाराजगी को एक मजबूत गठबंधन सरकार में बदलने में नाकाम रहे हैं. छोटी पार्टियों के साथ बातचीत करने, धार्मिक गुटों का समर्थन बनाए रखने और अपने विरोधियों के बीच मौजूद मतभेदों का फायदा उठाने की उनकी क्षमता अभी भी अहम है. साथ ही, इन नतीजों ने उनकी राजनीतिक रणनीति की सीमाएं भी उजागर कर दी हैं. जो सरकार बहुत मामूली संसदीय बहुमत पर टिकी हो, उसे सैन्य सेवा से छूट, बस्तियों से जुड़ी नीति, बजट और गाज़ा के भविष्य जैसे मुद्दों पर फिर से अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर ऑफ वेस्ट एशियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सिर कमर के अनुसार, अभी स्थिति यह है कि किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं. कमर ने ईटीवी भारत से कहा, 'लेकिन यह अभी भी बहुमत के आंकड़े से कम है, जिसका मतलब है कि सरकार बनाने के लिए उन्हें किसी दूसरी पार्टी या छोटे समूह के समर्थन की जरूरत होगी.' उन्होंने आगे कहा, 'सबसे बड़े गठबंधन के नेता के तौर पर, इजरायल के राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े गठबंधन के नेता को आमंत्रित करेंगे, जो कि नेतन्याहू का गठबंधन है. इसलिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार बनेगी. उन्होंने बताया कि इसके बाद नेतन्याहू को अपना बहुमत साबित करना होगा. कमर ने कहा, 'अगर वह बहुमत साबित करने में विफल रहते हैं, तो फिर दूसरे गठबंधन या पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. उन्हें भी अपना बहुमत साबित करना होगा. इस बीच, जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, तब तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे. कमर ने बताया कि देश में हंग पार्लियामेंट (त्रिशंकु संसद) जैसी स्थिति है. उन्होंने समझाया, 'जब तक कोई एक पार्टी या गठबंधन बहुमत साबित नहीं कर देता, तब तक एक कार्यवाहक सरकार बनी रहेगी. चुनावों में अरब समुदाय की ऐतिहासिक भागीदारी के कारण, अरब पार्टियां एक बेहतर स्थिति में आ गई हैं, हालांकि मैं उन्हें किंगमेकर तो नहीं कहूंगा. कमर ने आगे कहा कि इजराइल की कोई भी पार्टी अरब समुदाय के पूर्ण समर्थन और भागीदारी के साथ सरकार नहीं बनाना चाहेगी, क्योंकि ऐसा करना मुश्किल होगा. उन्होंने कहा, 'इसके लिए कुछ ऐसे समझौते करने पड़ सकते हैं, जिनके लिए शायद वे तैयार न हों. इसलिए, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।

रूसी ड्रोन से बचने गैस पाइपलाइनों में छिपे यूक्रेनी सैनिक

कीव, एजेंसी। रूस-यूक्रेन जंग अब अपने पांचवे साल में हैं। ऐसे में रूस के लगातार ड्रोन हमलों ने यूक्रेन के सैनिकों के लिए जमीन पर खुलेआम चलना मुश्किल कर दिया है। वे पुरानी गैस पाइपलाइनों के अंदर छिपकर रह रहे हैं। करीब 4 फीट चौड़ी इन सुरंगों में सैनिकों को कई हफ्तों से लेकर दो महीने तक गुजारने पड़ते हैं। कभी रूस से यूरोप तक गैस पहुंचाने वाली ये पाइपलाइन अब यूक्रेनी सैनिकों को खाना, हथियार और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने का रास्ता बन गई हैं।

रूस ने पहले किया था पुरानी पाइपलाइनों का इस्तेमाल : यूक्रेन के कुपियांस्क इलाके में पुरानी गैस पाइपलाइनों का करीब 129 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। पिछले साल के आखिर में रूसी सैनिक इन्हीं पाइपलाइनों के जरिए कुपियांस्क में घुसने में कामयाब हुए थे। इसके बाद यूक्रेनी सेना ने भी जमीन के नीचे से जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई। इसके बाद यूक्रेन की नेशनल गार्ड की खुफिया इकाई ने इन पाइपलाइनों के नक्शे जुटाए। साथ ही, इन्हें बनाने वाले पुराने गैस विशेषज्ञों की मदद से भूमिगत रास्तों का इस्तेमाल करने की योजना तैयार की। इसके बाद पाइपलाइनों में हवा पहुंचाने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया। यह इस पूरे काम का सबसे मुश्किल हिस्सा था।

दिन में पहुंचता है खाना और गोला-बारूद : इन पाइपलाइनों के जरिए सैनिकों तक खाना और गोला-बारूद पहुंचाया जाता है। इसके लिए छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। दिन में इन गाड़ियों से जरूरी सामान अंदर भेजा जाता है, जबकि रात में खुदाई से निकली मिट्टी की बोरियां बाहर लाई जाती हैं। सैनिक सिर्फ रात में ही कुछ समय के लिए बाहर निकल पाते हैं।

सैनिक संकरे रास्तों के कारण घुटनों पर रेंगते हैं : इन पाइपलाइनों के अंदर सैनिकों को काफी मुश्किल हालात में रहना पड़ता है। रास्ते इतने संकरे हैं कि उन्हें झुककर या घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। वहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है और न ही ताजी हवा मिलती है। शौचालय के लिए सैनिक प्लास्टिक के बैग और बोतलों का इस्तेमाल करते हैं। पाइपलाइनों में गैस के बचे हुए अंश, धूल और हवा की कमी भी उनके लिए खतरा पैदा करती है।

थर्मल इमेजिंग की वजह से पकड़े जाना आसान : ड्रोन और थर्मल इमेजिंग तकनीक ने खुले मैदान में सैनिकों की आवाजाही को बेहद खतरनाक बना दिया है। थर्मल इमेजिंग की मदद से ड्रोन जमीन पर मौजूद लोगों के शरीर की गर्मी पहचान सकते हैं।

ऐसे में सैनिकों के लिए छिपकर आगे बढ़ना भी आसान नहीं रह गया है। इसी वजह से यूक्रेन अपनी सेना के ठिकानों, निगरानी चौकियों और सामान रखने वाले केंद्रों को आपस में जोड़ने के लिए भूमिगत सुरंगों का नेटवर्क बनाने की संभावनाएं तलाश रहा है।

अटलांटा में जी20 विदेश मंत्रियों की वार्ता बेनतीजा खत्म, यूक्रेन युद्ध पर मतभेद से संयुक्त बयान अटका

अटलांटा, एजेंसी। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी20 के शीर्ष राजनयिक दो दिन की वार्ता के बाद शनिवार को कई अहम वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर आम सहमति बनाने में नाकाम रहे। रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर मतभेदों का असर अटलांटा में हुई बैठक की शुरुआत से ही दिखाई दिया। इस कारण समूह ने संयुक्त बयान जारी नहीं किया।

इसके बजाय अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बैठक के बाद अध्यक्ष का बयान जारी किया, जिसमें चर्चा का सार और ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा तथा समुद्री मार्गों से आवागमन की स्वतंत्रता जैसी प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया। इसमें किसी सहमति या समझौते की जानकारी नहीं दी गई। रुबियो ने कहा कि इन समस्याओं के सर्वमान्य समाधान के करीब पहुंचने का दावा नहीं किया जा सकता।

हालांकि, उन्होंने कहा कि जी20 के कुछ देश आपूर्ति शृंखला और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। रुबियो ने शुक्रवार को एकता की अपील के साथ वार्ता शुरू की थी, लेकिन रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मौजूदगी पर यूरोपीय राजनयिकों की आपत्ति के बाद विदेश मंत्रियों की पारंपरिक 'समूह तस्वीर' (ग्रुप फोटो) रद्द कर दी गई। यूरोपीय प्रतिनिधियों ने तस्वीर का बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी।

पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की ने कहा कि युद्धों में शामिल देशों के एक साथ मेज पर होने के कारण साझा रुख पर सहमति बनाना मुश्किल है। राजनयिकों के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजराइल का युद्ध, अमेरिकी शुल्क और दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों को लेकर मतभेद बने हुए हैं। बैठक के दौरान ईरान में अमेरिका के नए सैन्य हस्तक्षेप की आशंका भी चर्चा में रही। इससे सऊदी अरब सहित पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ी है। रुबियो ने शुक्रवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान से मुलाकात की थी।

'नेपाल: ट्रेकिंग के दौरान छह भारतीय पर्यटक लापता, भारी बर्फबारी के बीच सेना ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में भारी बर्फबारी के बाद छह भारतीय पर्यटक लापता हो गए हैं। इनमें दो महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं। सभी पर्यटक नेपाल की सबसे गहरी झीलों में से एक शे-फोक्सुंडो की ट्रेकिंग पर निकले थे। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी एएनआई को इसकी पुष्टि की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पर्यटक डोल्पो बुद्ध ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड नंबर चार और आठ से झील की ओर जा रहे थे। उन्हें आखिरी बार शे-फोक्सुंडो ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड चार और आठ के बीच स्थित नुमला पास और बागला पास के इलाकों में देखा गया था।

अभी क्यों हुई बर्फबारी : स्थानीय गाइडों को आशंका है कि बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात अर्नब के प्रभाव से हुई भारी बर्फबारी के कारण पर्यटक पहाड़ों में फंस गए हैं। बताया जा



रहा है कि स्थानीय लोगों ने उन्हें खराब मौसम और पहाड़ी दर्रों में खतरनाक परिस्थितियों को देखते हुए आगे नहीं बढ़ने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद पर्यटकों ने अपनी यात्रा जारी रखी। माना जा रहा है कि ऊंचाई वाले इलाके से लौटते समय वे बर्फ में फंस गए। डोल्पा की मुख्य जिला अधिकारी जुनू हमाल ने बताया कि पर्यटक फोक्सुंडो झील की ओर लौटते समय रास्ते में फंस गए। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने से पहले स्थानीय लोगों ने उन्हें मौसम और पहाड़ी रास्तों की कठिन परिस्थितियों के बारे में आगाह किया था।

पर्यटकों से संपर्क करना मुश्किल क्यों : शे-फोक्सुंडो ग्रामीण नगरपालिका के अध्यक्ष धावा समदुक गुरंग ने बताया कि पहाड़ी दर्रों में मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता। इससे लापता पर्यटकों से संपर्क करना मुश्किल हो रहा है। उनके मुताबिक वार्ड चार और आठ के बीच मोबाइल फोन सेवा नहीं है। ऐसे में पर्यटकों की मौजूदा स्थिति और उनके ठिकाने के बारे में जानकारी जुटाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। लापता पर्यटकों की तलाश के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि, भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण ऊंचाई वाले इलाकों में बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है। डोल्पा पुलिस उपाधीक्षक अनिल राज गिरि ने बताया कि ताजा जानकारी के मुताबिक, सभी छह भारतीय पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने संबंधित एजेंसी से बचाव अभियान में मदद के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। लापता पर्यटकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए नेपाली सेना की एक टीम भी तैनात की गई है। मोबाइल नेटवर्क की अनुपलब्धता, भारी बर्फ और दुर्गम पहाड़ी रास्तों के कारण बचाव दलों को पर्यटकों की सटीक लोकेशन पता लगाने में मुश्किल हो रही है। जिला प्रशासन कार्यालय के अनुसार, अपर डोल्पा पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 244 है। इनमें 149 नेपाली नागरिक, सार्क देशों के 44 पर्यटक और अन्य देशों के 51 पर्यटक शामिल हैं।

'इस्राइल जनादेश: पीएम चुनने का विधेयक ला सकता है विपक्षी दल, बदू महिलाओं ने कैसे पलटा नेतन्याहू का चुनावी पासा?

यरूशलम, एजेंसी। उम्म खालिद फतून पिछले साल युद्ध पीड़ितों के लिए बने एक यहूदी-अरब सहायता केंद्र में स्वयंसेवा करके लौटीं तो उन्होंने देखा कि बुलडोजर अजारनुग गांव में उनके बेटे के घर को ढहा रहे थे। पुलिस की निगरानी में आई टीम ने घर पर बुलडोजर चलाने से पहले फर्नीचर या सोलर पैनल तक हटाने का मौका नहीं दिया। अब, इस हफ्ते जब फतून को मौका मिला तो उन्होंने अपनी नाराजगी का जवाब इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ मतदान करके दिया। उनका सीधा निशाना राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-ग्विर थे जिन्होंने फलस्तीनी और अरब समुदाय के लोगों के घरों को व्यापक स्तर पर ढहाने का आदेश दिया था। फतून कहती हैं, बेन-



ग्विर को सत्ता से बाहर करना ही मेरा एकमात्र मकसद था। बदू समुदाय में ऐसा एक भी परिवार नहीं है जो हमारे खिलाफ उसके अभियानों से पीड़ित न हुआ हो। चुनाव से कुछ हफ्ते पहले फतून ने बदू महिलाओं को उनके अधिकारों और राजनीतिक ताकत के प्रति जागरूक करने के लिए जमीनी स्तर पर बाकायादा अभियान शुरू किया। इसके शानदार नतीजे भी दिखे, और चुनाव में दक्षिणी नेगेव इलाके के कुछ बदू गांवों में मतदान प्रतिशत तीन गुना तक बढ़ गया।

हमें अपने हर वोट की ताकत झोंकनी होगी : अल-नश्मियात अभियान का नेतृत्व करने वाली वकील हनान अलसनाह ने कहा, वर्षों के हिंसक शासन ने इस रूढ़िवादी समुदाय में बदलाव का दरवाजा खोल दिया है। हमने महिलाओं से कहा कि भले सभी पुरुष वोट दें फिर भी समुदाय का आधा हिस्सा ही होंगे। आपको अपने हर वोट की ताकत चाहिए, क्योंकि बेन-ग्विर के पास बहुत ताकत है।

62% से 93% तक दर्ज की गई वोटिंग : बदू समुदाय इस्राइली संसद नेसेट में अरब पार्टियों को 19 सीटें दिलाकर किंगमेकर की भूमिका में ला दिया। बदू समुदाय में सबसे कम मतदान 62% रहा, जबकि सबसे ज्यादा मतदान 93% दर्ज किया गया। उनके उत्साह से ही रआम पार्टी को चुनावी अनुमानों से काफी अधिक सफलता मिली। इस्राइल में सरकार गठन में राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए विपक्षी गुट अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर रहे बिना अल्पमत सरकार बनाने के लिए सीधे प्रधानमंत्री चुनने से संबंधित विधेयक लाने पर विचार कर रहा है। यह प्रस्ताव लागू होने पर मतदाता सरकार से अलग सीधे पीएम पद के लिए वोट डाल सकेंगे।

ट्रम्प की नेतन्याहू से फोन पर बात:बाद में बोले- ईरान के 1-2 ठिकाने और उड़ाना बाकी



वॉशिंगटन डीसी/तेल अवीव, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से शनिवार को फोन पर बातचीत की। यह जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी। इसके बाद रविवार को ट्रम्प ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े एक या दो ठिकाने अभी उड़ाना बाकी हैं। इनमें पिकैक्स माउंटेन भी शामिल है। वहीं, अमेरिकी न्यूज चैनल एमएस नाउ ने बताया कि वॉशिंगटन ने खाड़ी देशों को ईरान पर नए हमलों के लिए तैयार रहने को कहा है। ये हमले 4 नवंबर से शुरू हो सकते हैं। यह तारीख अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के अगले दिन की है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने हाल के हफ्तों में पश्चिम एशिया में हवाई सुरक्षा सिस्टम, गोला-बारूद और सैन्य उपकरणों की तैनाती बढ़ाई है। साथ ही, उसने अपने सैनिकों और सैन्य सामान को उन ठिकानों से दूसरी जगह भेजना शुरू कर दिया है, जहां ईरान हमला कर सकता है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का मानना है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड और इजराइल ने हमले की तैयारी कर ली है। इजराइली न्यूज चैनल च्रह के मुताबिक, पिछले हफ्ते अमेरिका के 10 सैन्य मालवाहक विमान इजराइल पहुंचे थे। इनमें हवाई हमलों से बचाव के लिए जरूरी उपकरण होने की बात कही जा रही है। इनका इस्तेमाल क्षेत्र में अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। इससे पहले, दो हफ्ते पहले इजराइल के कई लड़ाकू विमानों ने ईरान की सीमा तक उड़ान भरी थी और फिर वापस लौट आए थे। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह एक सैन्य अभ्यास का हिस्सा था। ट्रम्प इन दिनों 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के आखिरी प्रचार अभियान में जुटे हैं। इन चुनावों में अमेरिकी संसद के लिए प्रतिनिधि चुने जाएंगे। ईरान के साथ युद्ध और अमेरिका में ईंधन की बढ़ती कीमतें रिपब्लिकन पार्टी के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। ट्रम्प चुनाव के आखिरी दिनों में अपनी पार्टी के समर्थन को बढ़ाना चाहते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तारीख आगे बढ़ाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान भी अमेरिकी चुनाव से पहले बातचीत को जानबूझकर लंबा खींच रहा है।

'एस.जयशंकर: 'क्वाड देशों में चुनने की आजादी जरूरी', सप्लाई चेन और आर्थिक सुरक्षा पर और क्या बोले विदेश मंत्री?

अटलांटा , एजेंसी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को क्वाड के लिए 'चुनने की स्वतंत्रता', मजबूत सप्लाई चेन और गैर-बाजार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई को मुख्य प्राथमिकता बताया। इसके साथ ही, उन्होंने इस समूह के एजेंडे के लिए एक अधिक समकालीन और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। अटलांटा में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद, एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में जयशंकर ने उन प्रमुख मुद्दों का जिक्र किया, जिन पर उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ चर्चा की थी।

जयशंकर ने क्या कहा : समूह की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना, समृद्धि को बढ़ावा देना और पसंद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना हमारी निरंतर प्रतिबद्धताएं हैं।' उन्होंने टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत सप्लाई चेन बनाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहतर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

गैर-बाजार प्रथाओं का भी किया जिक्र : जयशंकर ने चर्चा के दौरान उठाई गई प्राथमिकताओं में इंडो-पैसिफिक में गैर-बाजार



प्रथाओं का मुकाबला करने और बढ़ते आर्थिक दबावों को भी शामिल किया। हालांकि, उनकी पोस्ट में किसी देश का नाम नहीं लिया गया और न ही यह बताया गया कि किन विशिष्ट प्रथाओं की बात हो रही है। क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, उन्होंने आतंकवाद-रोधी, समुद्री सुरक्षा और क्षमता निर्माण से जुड़े मौजूदा समझौतों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया, ताकि मजबूती बढ़ाई जा सके और शांति व स्थिरता को समर्थन मिले।

एआई को लेकर क्या चर्चा हुई : मंत्रियों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की तकनीकी और वित्तीय सहायता देने की इच्छा जताई। इसमें 'क्वाड एआई एक्सेलेरेटर' के माध्यम से दी जाने वाली मदद भी शामिल है। विज्ञप्ति में सुपर इंटेलिजेंस का भी जिक्र किया गया है, जिसके साथ एक फुटनोट में स्पष्ट किया गया है कि यह शब्द भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। मंत्रियों ने भारत और आसियान देशों में कचरे से महत्वपूर्ण खनिज निकालने की सुविधाओं के लिए वाशिंगटन द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने के वादे का स्वागत किया। यह राशि केवल भारत के लिए नहीं है। ये चारों साझेदार देश, इलेक्ट्रॉनिक कचरे और कबाड़ से खनिज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम की जा सके। वे रीसाइकल होने वाली सामग्रियों को एक देश से दूसरे देश भेजने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के तरीकों पर भी विचार करेंगे। समुद्री सहयोग के तहत, चारों देशों के प्रतिनिधियों ने 25 सितंबर से 7 अक्तूबर के बीच चेन्नई से पर्थ तक भारतीय तटरक्षक बल के एक गश्ती जहाज पर यात्रा की। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इनका सहयोग समुद्री और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण व उभरती प्रौद्योगिकियों, तथा मानवीय सहायता और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत ने जी20 को बताया कि ऊर्जा आपूर्ति का राजनीतिकरण बहुत हानिकारक है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

साणंद में अंधविश्वास का खौफनाक सच : मानसिक विक्षिप्त पिता ने 10 वर्षीय बेटे की दी बलि

साणंद, एजेंसी। अहमदाबाद जिले के साणंद तालुका के विंछिया गांव में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां मानसिक रूप से विक्षिप्त एक खेतिहर मजदूर नरेश पटेल ने अपने 10 वर्षीय इकलौते बेटे करण की बेरहमी से हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी ने शव के पास ही चैन की नींद सो गया। गुजरात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पत्नी भारतीबेन से किसी बात पर विवाद हो गया था, जिसके बाद वह अपने मायके चली गई थी। बेटा स्कूल जाने के कारण पिता के पास ही रह गया था। रविवार रात नरेश ने गुस्से और अंधविश्वास में आकर बेटे को पैरों से पकड़कर घर में बनी देवी की वेदी के सामने जमीन पर कई बार पटका और डंडे से सिर पर वार कर उसकी जान ले ली। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने पत्नी को बताया कि उसके पिता स्थानीय समुदाय में भुवा (देवी-देवता और लोगों के बीच मध्यस्थ) थे और उसने खुद भी यह भूमिका संभाली थी। उसने अंधविश्वास के चलते यह खौफनाक कदम उठाया ताकि भविष्य में परिवार में कोई और भुवा न बने।

महाराष्ट्र के 8 जिलों की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, एक साथ मिले ई-मेल से मचा हड़कंप

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र की न्याय व्यवस्था में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब राज्य के आठ जिलों की जिला एवं सत्र अदालतों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले। ठाणे, सातारा, सोलापुर, सांगली, बीड, हिंगोली, परभणी और अमरावती की अदालतों को निशाना बनाकर भेजे गए इन ई-मेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। एहतियात के तौर पर सभी संबंधित अदालतों की इमारतों को खाली करा लिया गया। धमकी भरे ई-मेल मिलने के तुरंत बाद वरिष्ठ न्यायाधीशों ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद न्यायाधीशों, वकीलों, कर्मचारियों और अदालत में मौजूद पक्षकारों को तत्काल बाहर निकाला गया। पुलिस, बम निरोधक एवं निष्क्रियकरण दस्ते (बीडीडीएस), डॉग स्क्वॉड और साइबर सेल की टीमें मौके पर पहुंचीं और अदालत परिसरों की सघन तलाशी शुरू की। ठाणे जिला अदालत को धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद ठाणे नगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर अदालत परिसर में आवाजाही पर नियंत्रण लगा दिया गया। वहीं, सातारा जिला न्यायालय में भी बम से इमारत उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बीड जिला एवं सत्र न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीशों को धमकी का ई-मेल मिलने के बाद वकीलों और पक्षकारों के बीच अफरा-तफरी मच गई। लोग आनन-फानन में अदालत परिसर से बाहर निकलने लगे। इसी तरह सोलापुर जिला न्यायालय में भी धमकी मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी इमारत को खाली कराया गया। हिंगोली में धमकी भरा संदेश मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ते ने न्यायाधीशों के चैंबर सहित सभी कक्षों की बारीकी से जांच की। अमरावती जिला एवं सत्र न्यायालय में भी पुलिस ने तत्काल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और पूरे परिसर की तलाशी ली। उधर, सांगली और परभणी जिला न्यायालयों को भी इसी तरह के धमकी भरे ई-मेल प्राप्त हुए। इसके बाद पुलिस, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते की टीमें अदालत परिसरों में पहुंचीं। सभी स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए सघन तलाशी अभियान चलाया गया। एक ही समय में राज्य के आठ जिलों की अदालतों को धमकी भरे ई-मेल मिलने से पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अब साइबर पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ये ई-मेल कहां से और किसने भेजे हैं। इसके पीछे किसी शरारती तत्व का हाथ है या फिर कोई बड़ी साजिश रची गई है, इसकी भी जांच की जा रही है।

चिदंबरम का नितिन नवीन से सवाल- 3 करोड़ घुसपैठिए हैं कौन, क्यों काटे 13.30 करोड़ नाम?

-कांग्रेस नेता ने घुसपैठियों की पहचान सार्वजनिक करने की मांग की

नई दिल्ली , एजेंसी। देश में घुसपैठियों की संख्या और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के देश में तीन करोड़ घुसपैठिए होने के दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल करते हुए सरकार से घुसपैठियों की पहचान सार्वजनिक करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की है।

चिदंबरम का सवाल है, कि भाजपा अध्यक्ष ने जिन तीन करोड़ घुसपैठियों की बात कही है, वे कौन हैं और क्या केंद्र तथा राज्य सरकारों ने उनकी पहचान कर ली है? यदि हरियाणा के लोगों को घुसपैठियों की जानकारी है तो राज्य सरकार उनके नाम सार्वजनिक कर कार्रवाई क्यों नहीं करती? इसी के साथ ही चिदंबरम ने कहा, कोई भी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा



है, लेकिन उनकी पहचान और संख्या को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए। चिदंबरम ने सवाल किया है, यदि देश में तीन करोड़ घुसपैठिए हैं तो एसआईआर के दौरान 13.30 करोड़ नाम क्यों हटाए गए? क्या हटाए गए सभी नाम मृत लोगों के थे? उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपील के बाद दोबारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले लोगों का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, हटाए गए नामों में से 91 से 93 प्रतिशत लोगों ने अपील में सफलता हासिल की। उन्होंने पूछा कि क्या ये लोग भी घुसपैठिए थे?

कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप

दूसरी ओर, नितिन नवीन ने कांग्रेस पर चुनावी नतीजों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और केरल में जीत मिलने पर कांग्रेस लोकतंत्र को सही मानती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हारने पर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाती है। नवीन ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर केवल राजनीतिक मुद्दे खड़े कर रही है। उन्होंने बिहार में बूथ लेवल एजेंटों की मौजूदगी और शिकायतों का हवाला देते हुए कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए।

महादेव एप मामले में सौरभ चंद्राकर का प्रत्यर्पण: सीएम साय ने बताया बड़ी सफलता

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महादेव ऑनलाइन सट्टा एप घोटाले के कथित सरगना सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण को बड़ी सफलता बताया है। दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए, मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उससे पूछताछ के बाद उन लोगों की पहचान सामने आएगी, जिन्हें इस अवैध सट्टा सिंडिकेट से प्रोटेक्शन मनी मिलता था। उन्होंने कार्रवाई के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने चंद्राकर को ओमान से भारत वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीबीआई अधिकारियों ने बताया था कि एजेंसी ने छह हजार करोड़ रुपये के कथित महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप घोटाले के सिलसिले में चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कराया है। सीबीआई की टीम आरोपी चंद्राकर को भारत लेकर आई थी और सोमवार को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। चंद्राकर दो सीबीआई मामलों और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक मामले में वांछित था, जिसमें पहले ही आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। उसके खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद सीबीआई और ईडी के औपचारिक अनुरोध पर प्रत्यर्पण संभव हो पाया। जांच में खुलासा हुआ है कि महादेव ऑनलाइन बुक देश के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट में से एक था, जिसे भारत के बाहर से फ्रेंचाइजी पैनलों के जरिए संचालित किया जा रहा था।

राहुल गांधी खुद आज लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती: सुधांशु त्रिवेदी

- राहुल के आने से पहले कांग्रेस कई राज्यों में शून्य

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में गलत नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाकर कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। बीजेपी सांसद त्रिवेदी ने टिप्पणी करते हुए विपक्ष की उस प्रवृत्ति पर सवाल उठाया, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति और बढ़ती राष्ट्रीय गौरव की भावना से खुश नहीं दिखते। बीजेपी सांसद त्रिवेदी ने कांग्रेस के कई राज्यों में लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओडिशा में बीते 25 वर्षों से, गुजरात में 1995 से और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 1990 के दशक से सत्ता से बाहर है। इन राज्यों में कुल 120 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी के सत्ता-विरोधी लहर (एंटी-इनकम्बेंसी) के दावे को खारिज कर कहा कि वास्तविकता इससे काफी अलग है।



बीजेपी त्रिवेदी ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि उनकी पार्टी, उनके राजनीति में आने से बहुत पहले ही, उन राज्यों में भी 10 सीटें जीतने की स्थिति में नहीं थी जहाँ कुल 230 लोकसभा सीटें आती हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि कांग्रेस उन 230 सीटों में पहले से ही कमजोर थी, तब शेष 300 सीटों में से 272 जीतने की उम्मीद कैसे हो सकती थी? यह आंकड़ा कांग्रेस की वास्तविक स्थिति को दिखाता है और चुनावी परिणामों पर उनके गलत नैरेटिव को बेनकाब करता है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलएस) की भूमिका पर भी प्रश्नचिह्न लगाया। उन्होंने पूछा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया की निगरानी में उनकी क्या भूमिका थी। त्रिवेदी ने स्पष्ट किया कि जहां चुनाव आयोग सरकारी कर्मचारियों (बीएलओ) के माध्यम से मतदाता सूची को अपडेट करता है, वहीं राजनीतिक दल अपने बीएलओ नियुक्त करते हैं ताकि इस प्रक्रिया पर नज़र रखी जा सके। पूरे देश में, चुनाव आयोग द्वारा 12 लाख बीएलओ और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा 22 लाख बीएलए नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी सांसद त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का मौजूदा रवैया न केवल तथ्यों से परे है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक गंभीर चुनौती भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि वे चुनावी प्रक्रियाओं पर गलत धारणाएं फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।

यूपी चुनाव 2027 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, पीएम मोदी की 18 मंडलों में होंगी रैलियां

बीजेपी के चाणय अमित शाह संभालने वाले हैं चुनावी रणनीति

लखनऊ, एजेंसी । उत्तरप्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अभी से तैयारियां तेज करने की रणनीति तैयार की है। दिवाली के बाद पार्टी प्रदेश में तीन स्तरों पर व्यापक चुनावी अभियान शुरू करने की तैयारी में है। नवंबर और दिसंबर के दौरान चलने वाले अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका होगी। पार्टी का लक्ष्य चुनाव से काफी पहले प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक पकड़ मजबूत करना है।

सूत्रों के मुताबिक, भाजपा की प्रस्तावित रणनीति के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने वाले है। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के सभी 18 प्रशासनिक मंडलों में बड़ी रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। इन रैलियों के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने, मतदाताओं तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने और भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश की जाएगी। पार्टी चाहती है कि उसका संदेश प्रदेश के हर प्रमुख क्षेत्र तक सीधे पहुंचे।

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री शाह चुनावी रणनीति और संगठनात्मक तैयारियों की कमान संभालने वाले है। उनके नेतृत्व में अलग-अलग जिलों और क्षेत्रों में रैलियां तथा बूथ स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संगठन के जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष ध्यान होगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधानसभा क्षेत्र स्तर पर अभियान को गति देने वाले है। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम, रैलियां और संगठनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी भी अभियान का महत्वपूर्ण चेहरा है। वह जिला स्तर पर रैलियां कर सभी विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे है। बताया जा रहा है कि 20 नवंबर के बाद अभियान पूरी गति पकड़ सकता है। इसके लिए पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत प्रत्येक बूथ कार्यकर्ता और छोटी टीम को कम से कम 50 परिवारों तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी जाएगी। कार्यकर्ता घर-घर जाकर भाजपा सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाले है। इस चुनावी रणनीति में युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को भी विशेष महत्व दिया गया है। पार्टी इन मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करने और सरकार की योजनाओं से जोड़ने पर जोर देगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया जाएगा। स्थानीय कार्यकर्ताओं को रैलियों, जनसभाओं और क्षेत्रीय कार्यक्रमों की तस्वीरें, वीडियो और अपडेट साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भाजपा की इस तीन स्तरीय रणनीति का मकसद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में संगठन को मजबूत करना और व्यापक जनसमर्थन जुटाना है।

सोनिया की लालू से मुलाकात, तेजस्वी ने कहा... चुनौतियों के लिए एकजुट हो विपक्ष

नई दिल्ली,एजेंसी। नई दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इस दौरान राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे, जिन्होंने देशभर में विपक्षी दलों को एकजुट होकर वर्तमान चुनौतियों का सामना करने का आह्वान किया। यह मुलाकात दिल्ली स्थित लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती के आवास पर हुई। तेजस्वी ने बताया कि लालू यादव नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली आए हुए थे। रविवार को उनकी सोनिया गांधी से फोन पर बात हुई थी और लालू प्रसाद के दिल्ली में होने की जानकारी मिलने पर सोनिया गांधी ने स्वयं उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद यह भेंट हुई। उन्होंने दोनों परिवारों के बीच दशकों पुराने मधुर संबंधों का जिक्र कर कहा कि सोनिया गांधी और लालू प्रसाद ने हमेशा एक-दूसरे के कठिन समय में सहयोग किया है। यह एक लंबे अंतराल के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात थी। तेजस्वी ने विपक्षी एकजुटता पर जोर देकर कहा कि केवल बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में विपक्षी दलों को एक साथ आकर मजबूती से चुनौतियों का सामना करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सभी विपक्षी दल एकजुट नहीं होते हैं, तब तक वर्तमान लड़ाई को जीता नहीं जा सकता। उनका यह बयान विपक्षी इंडिया गठबंधन की मजबूती के प्रयासों के बीच आया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रखी, जिसमें कहा कि जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक विपक्ष चुप नहीं बैठेगा और उनका संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में हाल ही में हुई रैली को फ्लॉप बताने के दावों को खारिज कर तेजस्वी ने कहा कि विरोधी बेचैन और परेशान हैं, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग लोकतंत्र को कुचलकर उसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। महाभारत की लड़ाई और कृष्ण के बारे में पूछने पर उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि पहले शकुनि को जान लीजिए।

जयशंकर ने दो टूक सुनाया, भारत की विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं चलेगी

नई दिल्ली , एजेंसी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी विदेश नीति किसी दूसरे देश के दबाव या निर्देशों से तय नहीं होगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और रूस से तेल खरीदने जैसे मुद्दों पर भारत का रुख मजबूती से रखा है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर स्वतंत्र फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके रुख को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दबाव की राजनीति के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है।

अटलांटा में आयोजित जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक और क्वाड से जुड़ी बातचीत के दौरान भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर दिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की क्वाड बैठक में जयशंकर के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल हुईं।

बैठक के दौरान जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किसी भी देश पर दबाव बनाने की नीति को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया। खासकर रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत ने कहा है कि उसकी ऊर्जा नीति देश की जरूरतों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होती है। अमेरिका के साथ क्वाड जैसे महत्वपूर्ण मंच पर साझेदारी होने के बावजूद भारत हर मुद्दे पर वाशिंगटन के विचारों से सहमत होने के लिए बाध्य नहीं है।

जयशंकर ने वैश्विक संघर्षों का मुद्दा उठाकर कहा कि युद्धों और अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी आर्थिक और अन्य कीमत चुकानी पड़ती है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत अपना सख्त रुख दिखाया है। जयशंकर स्पष्ट कर चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस भारत की नीति है और इस मामले में किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत का रुख चीन और अमेरिका सहित सभी वैश्विक शक्तियों के लिए स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि नई दिल्ली अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करेगी। रणनीतिक साझेदारी के बावजूद राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।



राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नवीन का भागलपुर में ऐतिहासिक स्वागत

आतिशबाजी और बुलडोजर से पुष्पवर्षा

भागलपुर, एजेंसी । भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का, पदभार संभालने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचने पर, ऐतिहासिक और भव्य स्वागत हुआ। हवाई अड्डे से लेकर लाजपत पार्क तक पूरे रास्ते में उत्सव का माहौल छाया रहा, जहाँ फूलों की पंखुड़ियों की बारिश, ढोल-नगाड़ों की थाप और गगनभेदी आतिशबाजी ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में अद्भुत ऊर्जा का संचार किया।



कार्यकर्ताओं के उत्साह का आलम यह था कि कई स्थानों पर बुलडोजर पर चढ़कर काफिले पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गईं, कहीं फूल-मालाओं और गुलदस्तों से शीर्ष नेता का अभिनंदन हुआ। सड़क के दोनों ओर कतारबद्ध खड़े कार्यकर्ताओं और जनसमूह ने स्वागत समारोह को विशाल शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन सुबह हेलीकॉप्टर से भागलपुर हवाई अड्डे पर उतरे, उनके साथ उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने पौधा भेंट कर औपचारिक अगवानी की। इसके बाद भाजपा और जदयू के वरिष्ठ स्थानीय नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने शॉल ओढ़ाकर, बुके और फूलों की माला पहनाकर उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया।

हवाई अड्डे पर बने वीआईपी लाउंज में कुछ देर ठहरने के बाद उनका काफिला निर्धारित कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुआ। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही स्वागत और भी भव्य हुआ। गाजे-बाजे के बीच कई बुलडोजरों से काफिले पर लगातार फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गईं, और आतिशबाजी व गगनभेदी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को फूल-मालाओं से लाद दिया। इसके बाद काफिला तिलकामांझी, आदमपुर होते हुए लाजपत पार्क पहुंचा, जहां भी हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन और वीवीआईपी प्रोटोकॉल को देखकर भागलपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षा के कड़े और चाक-चौबंद इंतजाम किए थे। जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारी सुबह से ही अलर्ट मोड पर तैनात रहे, जिसमें जिलाधिकारी पांडेय ने व्यवस्थाओं की कमान संभाली, और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव सुरक्षा तंत्र की सीधी निगरानी कर रहे थे। सदर एसडीएम सुनील कुमार व एडीएम राकेश रंजन सहित वरीय अधिकारी भी पल-पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए थे।

शिवसेना नेता आनंद का दावा- फ्लॉप शो साबित हुई विपक्ष की रैली

- केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विपक्ष पर साधा निशाना

नई दिल्ली, एजेंसी । दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित इंडिया गठबंधन की महारैली को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुई इस रैली में कांग्रेस ने 10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया था। हालांकि, भाजपा नेताओं के बाद अब शिवसेना नेता आनंद दुबे भी इस रैली को फ्लॉप शो बता दिया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता और पूर्व में उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता रहे आनंद दुबे का कहना है, कि रैली में व्यापक तैयारियों के बावजूद केवल 50 से 60 हजार लोग ही पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल लोकतंत्र बचाने के नाम पर अपने परिवार, संपत्ति और राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए रैलियां कर रहे हैं।

बीजेपी में शामिल हुए 3 बागी विधायकों पर आप का हमला, बीजेपी को मुबारक हो यह कचरा

लुधियाना, एजेंसी । पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। आप पार्टी के तीन बागी विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौरामाजरा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हुए हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने तीनों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है।

आप नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भाजपा में शामिल हुए विधायकों पर निशाना साधकर कहा कि भाजपा की आदत कचरा इकट्ठा करने की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए 117 उम्मीदवार भी नहीं हैं और उसका संगठन खोखला है। भारद्वाज के मुताबिक, पार्टी उन नेताओं को आगामी चुनाव में टिकट नहीं देगी, जिनके खिलाफ नकारात्मक फीडबैक मिला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा चाहे, तब इन नेताओं को टिकट दे सकती है, इससे आम आदमी पार्टी को कोई परेशानी नहीं है।

उधर, भाजपा ने तीनों नेताओं का पार्टी में स्वागत कर पंजाब में अपनी राजनीतिक मजबूती के लिए अहम बताया है। पार्टी का कहना है कि इन नेताओं का राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक



अनुभव पंजाब में भाजपा के मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। पूर्व आईपीएस अधिकारी और अमृतसर नॉर्थ से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पंजाब विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान को भेज दिया है।

इसके पहले समाना के विधायक चेतन सिंह जौरामाजरा और सनौर के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने भी पार्टी छोड़ दी थी। भाजपा में शामिल होने के बाद कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कहा कि पंजाब में शांति और समृद्धि की वापसी केवल भाजपा ही करा सकती है। चुनाव से पहले इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।